www.deshbandhu.co.in खबरें लगातार ... | पत्र नहीं; मित्र | संपर्क : deshbandhubpl1@gmail.com

देशबन्धु

वर्ष – 37 । अंक – 164 । भोपाल, मंगलवार, 16 जून 2026 । पृष्ठ–8 । मूल्य – 2.00 रुपए

सार-समाचार

राज्य में कक्षा पांचवीं-आठवीं की पुनः परीक्षा आज से

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश में कक्षा पांचवीं और आठवीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू होकर 23 जून तक चलेगी। इसमें मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल होंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने 2,795 परीक्षा केन्द्र बनाए हैं। कक्षा पांचवीं के 1.17 लाख तथा आठवीं के 1.32 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रों पर ही मुद्रित किए जाएंगे।

विस्तृ2 समाचार पृष्ठ 3 पर

कांगो में इबोला से 181 मौतें, 782 मामलों की पुष्टि हुई

किन्शासा, एजेंसी। कांगो में अब तक इबोला से 181 मौतें हो चुकी है और पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 782 हो गई है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार शाम को 'एक्स' पर यह जानकारी दी। कांगो में मामलों की संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है, क्योंकि इस बीमारी के फैलने की पुष्टि 15 मई को हुई थी। इसके अलावा, संक्रमितों के संपर्क में आये लोगों की तलाश की दर भी महज 56 फीसदी है। इबोला का यह नया प्रकोप दुर्लभ 'बुंडीबुग्यो वायरस' से फैला है। इसकी कोई स्वीकृत वैक्सीन या इलाज अभी उपलब्ध नहीं है।

प्रकाश राज के खिलाफ तिरुपति अदालत में शिकायत

तिरुपति, एजेंसी। अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ तिरुपति के एक कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला उनकी कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं और रामायण पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिनेता ने सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान दिए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यह शिकायत भाजपा नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य जी. भानुप्रकाश रेड्डी ने दर्ज कराई है। उन्होंने तिरुपति की एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में यह मामला सोमवार को दाखिल किया।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार यानी 15 जून से आधिकारिक तौर पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गईं, जिससे उत्तरी भारत में हवाई संपर्क को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) से उड़ान संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। एयरलाइन के अनुसार, पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जबकि इसके कुछ ही समय बाद पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई।

ट्रंप ने किया ऐलान, होर्मुज खोलने को भी मंजूरी, गरीबाबादी ने भी की पुष्टि

अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर सहमत

- दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक समारोह में करेंगे हस्ताक्षर
- पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा समझौता

अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने का भी आदेश देता हूं। दुनिया भर के जहाज अब अपनी यात्रा शुरू करें।
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका

समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार हो गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
काजेम गरीबाबादी उप विदेश मंत्री, ईरान

वाशिंगटन, 15 जून (एजेंसियां)। पश्चिमी एशिया में युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर सहमत हो गये है। दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक समारोह में इसपर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर रविवार देर रात इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा, 'ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ समझौता अब संपन्न हो चुका है। सभी को बधाई! मैं होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बिना किसी शुल्क के पूरी तरह खोलने की अनुमति देता हूं। साथ ही, अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने का भी आदेश देता हूं। दुनिया भर के जहाज अब अपनी यात्रा शुरू करें। तेल का प्रवाह फिर से शुरू होने दें।' ईरान ने भी अमेरिका के साथ समझौते को लेकर पुष्टि की है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि इस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा, 'समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार हो गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।' श्री गरीबाबादी ने कहा कि इस ज्ञापन में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर आज रात से सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने की बात भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक अन्य पोस्ट में कहा, 'यह ऐतिहासिक समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। मुझसे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पहली बार क्षेत्र के नेताओं को ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें वास्तविक और स्थायी शांति दिलाने में मदद कर सकता है।' श्री ट्रंप ने बताया कि आगामी शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य खोल दिया जाएगा ताकि वहां बिछी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाया जा सके। इसके बाद क्षेत्र के दोनों ओर से तेल की आपूर्ति फिर से सामान्य हो जाएगी, जिसका लाभ न केवल इस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा।

ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा: वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने गतिरोध के एक प्रमुख बिंदु यानि परमाणु हथियारों के लेकर कहा कि समझौता यह सुनिश्चित करता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। श्री वेंस ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, 'इसका मतलब है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। वह न तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और न ही उन्हें खरीदने या हासिल करने की कोशिश करेगा। यह बात इस समझौते में शामिल है।' अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका इस बात पर नजर रखेगा कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है या नहीं। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि इसके बदले ईरान को क्या मिलेगा।

28 फरवरी को शुरू हुई थी जंग

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई जंग के पहले दिन ही मारे गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया. 8 अप्रैल 2026 को यूएस ईरान के बीच सीजफायर पर सहमति बनी थी। इसके बाद शांति समझौते को लेकर मध्यस्थों के जरिए बातचीत की जा रही थी। जून में इसी सप्ताह तब हालात और नाजुक हो गए। जब ईरान द्वारा यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने के बाद दोबारा हमले शुरू हुए थे।

शरीफ ने अमेरिका और ईरान का किया धन्यवाद

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। श्री शरीफ ने कहा, 'हम इस विवाद का कूटनीतिक समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका और ईरान का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम इस समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए मध्यस्थता की कोशिश में शामिल कतर के महान नेतृत्व का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सऊदी अरब और तुर्की के दूरदर्शी नेतृत्व का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है।'

कोटा में कल प्रतिरोध का बिगुल फूंकेंगे राहुल

- शिक्षा बचाओ-भविष्य बचाओ नारे के साथ होगी छात्रों की महारैली
- एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी

नई दिल्ली देशबन्धु। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रतिरोध आंदोलन की शुरुआत बुधवार को राजस्थान के कोटा शहर से होने वाली है। इसके लिए उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिस पर नारा लिखा है- ' शिक्षा बचाओ-भविष्य बचाओ।' इससे साफ है कि राहुल का आंदोलन महज पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है।

उनके एजेंडे में समूची शिक्षा व परीक्षा प्रणाली, शिक्षा का बाजारीकरण और शीर्ष स्तर पर जवाबदेही आदि शामिल हैं। इस आयोजन की तैयारी में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस व पार्टी की जिला इकाई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने अभियान के बारे में राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इसकी शुरुआत कोटा से होगी, फिर इसे देश के हर कोने में फैलाया जाएगा। उनका कहना है कि जब सरकार सुनने को तैयार न हो तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है। 'आइए सब मिलकर ऐसी हुंकार बने, जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो।' उल्लेखनीय है कि राहुल ने अब तक कई आंदोलन और यात्राएं की हैं, लेकिन उनके इस प्रतिरोध आंदोलन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वे अपनी पार्टी को उस तेवर में ले जाना चाहते हैं, जिसमें उसने अंग्रेजों से लोहा लेकर भारत को आजाद कराया था। इसका संकेत उन्होंने आठ जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अपने भाषण में दिया था। उनका कहना था कि कांग्रेस प्रतिरोध से पैदा हुई पार्टी है, जो इस विचारधारा का समर्थन करती है कि सभी भारतीय एक समान हैं।

राहुल ने अपने बयान में कहा है कि अब देश में मेहनत का फल नहीं मिलता और सपने देखने पर सजा मिलती है।

प्रदर्शन कर रहे दीपके के साथ हुई धक्का-मुक्की

जयपुर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ जयपुर में प्रदर्शन के दौरान धक्का-मुक्की और हंगामे की घटना सामने आई है। सोमवार को शहीद स्मारक पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया।

चुनाव आयोग को टीएमसी सांसदों ने दी विलय की जानकारी

एनसीपीआई दल की प्रमुख बनीं काकोली

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने सोमवार को एक और बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए अपनी नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय की औपचारिक सूचना चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ईसीआई) को दे दी है. साथ ही, बागी गुट ने काकोली घोष दस्तीदार को पार्टी का नया प्रमुख चुने जाने की जानकारी भी आयोग को दी है।

टीएमसी के बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार को वैसे तो टीएमसी बागी गुट के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष भी अपना नेता बनाए जाने की जानकारी रविवार को दे दी थी, मगर सोमवार को बागी गुट की तरफ से इसकी औपचारिक चिट्ठी भी चुनाव आयोग को सौंप दी गई. टीएमसी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों (20 में से) के समर्थन के साथ यह विलय दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत किया गया है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले ही अलग बैठक व्यवस्था के लिए पत्र सौंपा था. अब चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में विलय की पुष्टि के साथ काकोली घोष को एनसीपीआई की नई अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का भी ऐलान कर दिया गया है. काकोली घोष दस्तीदार के अनुसार, एनसीपीआई में आधिकारिक विलय कर लिया गया है. हम अब एनडीए के साथ मिलकर देश और बंगाल के विकास के लिए काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नई शुरुआत है। एनसीपीआई, पहले एक छोटी त्रिपुरा-आधारित क्षेत्रीय पार्टी थी, अचानक 20 लोकसभा सांसदों के साथ संसद में मजबूत स्थिति में आ गई है।

दीपक को दोबारा मंत्री बनाए जाने पर मांगा जवाब

पटना, एजेंसी। बिहार की राजनीति से जुड़ा एक अहम मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर सुनवाई हुई है। सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे मंत्री पद पर बने नहीं रह सकते। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई भी गैर-विधायक व्यक्ति अधिकतम छह महीने तक ही मंत्री रह सकता है और इस अवधि में उसे विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। याचिकाकर्ता के वकील सुदीप चंद्रा और सान्या कौशल ने दलील दी कि दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री नियुक्त किया था।

साइबर सुरक्षा कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, कहा

सीमाओं की तरह महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा

महू में स्थापित किया जाएगा साइबर सुरक्षा अनुसंधान केन्द्र

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा मध्यप्रदेश बदलते दौर में हर तरह की की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी नए दौर में नई तकनीक की चुनौतियां हमने देखी हैं। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आयोजित परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में ठोक कदम उठाते हुए राज्य में साइबर सुरक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने डाटा सुरक्षा को सीमाओं की सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। जो केंद्रीय साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साइबर अटैक की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में इसकी महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम साबित होगी। उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। डॉ. यादव ने कहा कि जनधन खाते खुलने का परिणाम यह रहा कि देशभर में जरूरतमंदों को सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाने लगा। एक समय जब 1 रुपए में 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच रहे थे। डीबीटी की पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से शत प्रतिशत लाभ हितग्राहियों तक पहुंचने लगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए डेटा की सुरक्षा सीमा की सुरक्षा के बढ़कर है। सुरक्षा के तमाम चाकचौबंद उपायों के बाद भी अगर जीवनभर की गाढ़ी कमाई एक झटके में कोई साइबर अपराधी उड़ा ले जाए तो दुख होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साइबर क्राइम के अदृश्य राक्षसों के खिलाफ देवदूत तैयार कर सभी आवश्यक प्रबंधन करना वर्तमान दौर की जरूरत है। दुनिया ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम का लोहा माना है।

ईंधन और अनाज की कीमतों ने बिगाड़ा बजट

खुदरा के बाद अब थोक महंगाई की मार

मई में थोक महंगाई 9.68 प्रतिशत दर्ज की गई

नई दिल्ली, एजेंसियां। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को 2022-23 को नया आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) सीरीज लॉन्च की, साथ ही मंत्रालय ने बताया कि मई में थोक महंगाई दर 9.68 प्रतिशत दर्ज की गई। नई डब्ल्यूपीआई सीरीज ने 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी सीरीज की जगह ले ली है। यह देश में उत्पादक मूल्य माप प्रणाली (प्रोड्यूसर प्राइस मेजरमेंट) में किए जा रहे व्यापक बदलाव का हिस्सा है। संशोधित डब्ल्यूपीआई के साथ सरकार ने आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (ओपीपीआई), ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (आईपीपीआई) और सात सेवाओं के लिए सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) की नई सीरीज भी जारी की है। मंत्रालय के अनुसार, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की ओर यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सिफारिशों और वैश्विक मानकों के अनुरूप है। उपयोगकर्ताओं को नई प्रणाली अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से डब्ल्यूपीआई सीरीज को अगले पांच वर्षों तक जारी रखा जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक, मई में अखिल भारतीय डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर सालाना आधार पर 9.68 प्रतिशत रही, जबकि सभी वस्तुओं का सूचकांक बढ़कर 109.9 पर पहुंच गया। प्रमुख श्रेणियों में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर मई में बढ़कर 4.99 प्रतिशत हो गई। वहीं, ईंधन और बिजली (फ्यूल एंड पावर) श्रेणी में महंगाई लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि विनिर्मित उत्पादों (मैन्यूफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स) की महंगाई दर इसी अवधि में बढ़कर 7.48 प्रतिशत दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद तथा बेसिक मेटल्स, अनाज, थोक महंगाई बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में शामिल रहे।

मोदी का वंदे मातरम की प्रस्तुति से स्वागत

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मिले मोदी

- रॉबर्ट फिको को भारत आने का न्योता दिया

पेरिस/ब्रातिस्लावा, (एजेंसियां)। भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते व्यापक साझेदारी तक बढ़ाए गए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकियन पीएम रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय डिफेंस और ट्रेड डील हुई। ब्रातिस्लावा के महल में स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको से मुलाकात के बाद मोदी ने फिको को भारत आने का न्योता भी दिया। स्लोवाकियन पीएम फिको ने मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और इस उपलब्धि को राजनीतिक चमत्कार बताया। पीएम मोदी दो देशों के दौरे के दूसरे फेज में रविवार रात 2:18 बजे स्लोवाकिया पहुंचे। राजधानी ब्रातिस्लावा में विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराय ब्लानार ने उनका स्वागत किया। मोदी को पारंपरिक स्लोवाक रीति से ब्रेड और नमक भेंट किया गया, जिसे यहां आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। मोदी ने एयरपोर्ट पर स्लोवाकिया में मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात की। दरअसल, मोदी 13 जून से फ्रांस-स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर हैं। वे 17 जून को फ्रांस के एवियान में जी-7 समिट में शामिल होंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी मिल सकते हैं।

11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए : भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सार-समाचार

चित्रकूट दर्शन को निकले 3 दोस्तों की मौत

बांदा, देशबन्धु। अमावस्या पर चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे तीन दोस्तों की रविवार देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। हादसा बिसंडा क्षेत्र में रात करीब 12 बजे हुआ, जहां उनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान संजय, रामबाबू पटेल और अरविंद रैकवार निवासी ग्राम कोरारी, थाना बिसंडा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। सीओ यातायात सौरभ सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनना हादसे के प्रमुख कारण प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए एक्सप्रेसवे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की है।

चंद्रावल नदी में समाए 3 मासूम

बांदा, देशबन्धु। जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी गांव में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में सगे भाई-बहन अंश (10) और माधुरी (13) के साथ उनका फुफेरा भाई प्रतीक (10) शामिल है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, चार भाई-बहन सुबह चंद्रावल नदी में नहाने गए थे। बड़ा भाई सिद्धार्थ नदी किनारे बैठा था, जबकि माधुरी, अंश और प्रतीक नदी में उतर गए। नहाते समय तीनों बच्चे नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गए और तेज बहाव में डूबने लगे। सिद्धार्थ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीनों पानी में समा चुके थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश अभियान चलाया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें माधुरी नदी किनारे सेल्फी मोड में वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दोनों बच्चे नदी में तैरते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो अब परिवार और ग्रामीणों के लिए अंतिम याद बन गया है। मृतकों की मां सुनयना और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में एक साथ तीन बच्चों की मौत से मातम पसरा हुआ है।

करीला में जुएं की बड़े फड़ों पर कार्रवाई

पुलिस का 2 स्थानों पर छापा : 12 जुआरी गिरफ्तार, 47 हजार से अधिक नगदी जब्त

सेवढ़ा, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे तथा एसडीओपी सेवढ़ा अजय चानना के मार्गदर्शन में थाना भगुवापुरा पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर संचालित जुए के फड़ों पर दबिश देकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 47,300 रुपये नगद एवं ताश की गड्डियां जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ शातिर जुआरी स्थान बदल-बदलकर जुए का संचालन कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी भगुवापुरा ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी सेवढ़ा एवं थाना प्रभारी द्वारा गुप्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर रात्रि में रेकी की गई तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से न केवल दतिया जिले बल्कि सीमावर्ती भिंड जिले के आलमपुर एवं दबोह क्षेत्र में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। सबसे पहले पुलिस ने मौजा करीला स्थित जसवंत भदौरिया के खेत में संचालित जुए के फड़ पर दबिश दी। यहां से सात आरोपियों को जुआ खेलते हुए

पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से कुल 33,500 रुपये नगद एवं 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में रवि कुमार प्रजापति निवासी आलमपुर, सुनील बघेल निवासी गोरा, वीर बहादुर जाटव निवासी रतनपुरा, अजय परिहार निवासी गोरा, रविंद्र कुशवाह निवासी गोरा, प्रदीप खेमरिया निवासी गांगेपुरा तथा संतोष जाटव निवासी जोरी शामिल हैं। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने रामजानकी मंदिर के पास स्थित पुनीत पटेल के खेत में दबिश दी, जहां पांच लोग जुआ खेलते हुए पाए गए। मौके से 13,800 रुपये नगद एवं 52 पत्तों की ताश जब्त की गई। इस कार्रवाई में आदिल खान, विक्रम जाटव, बसीर खान निवासी इंदरगढ़, राहुल गुर्जर निवासी परसौदा गुर्जर तथा कल्लू उर्फ रामकिशोर सेन निवासी छोटा आलमपुर को गिरफ्तार किया गया। दोनों स्थानों पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 47,300 रुपये नगद एवं दो ताश की गड्डियां जब्त की हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी भगुवापुरा शाकिर अली खान के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक रवि दुबे, उदय यादव, रामलाल पाल तथा आरक्षक हरिमोहन, हनुमान, संदीप, दिलीप, खेमान, हरजेन्द्र, सैनिक रामरतन एवं सैनिक संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सिंध नदी के पवित्र तट पर सुबह से लगी कतारें, यातायात व्यवस्था चरमराई

सोमवती अमावस्या पर सनकुआं धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

सेवढ़ा, देशबन्धु। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सेवढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल सनकुआं धाम में सोमवार को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सिंध नदी के पवित्र तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर भगवान के दर्शन किए तथा परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की।

मेले में धार्मिक आस्था के साथ-साथ उत्साह और उल्लास का माहौल भी देखने को मिला। परिसर में पूजन सामग्री, खिलौने, खाद्य पदार्थों और अन्य दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी मेले का आनंद लेते नजर आए। सिंध नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल दिनभर बनी रही।

हालांकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित नजर आई। इतना ही नहीं नगर परिषद की व्यवस्था की कमी रही जबकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं ना तो उन्हें शौचालय ना ही महिला सिर्फ दलों के लिए कपड़ा बदलने की व्यवस्था और ना ही साफ सफाई।

सनकुआं धाम की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आश्चर्य की बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद मौके पर यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल अथवा ट्रैफिक कर्मी दिखाई नहीं दिए।

स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा पूर्व से ही यातायात प्रबंधन के उचित इंतजाम किए जाते तो लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कई स्थानों पर जाम जैसी स्थिति बनने से वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से मांग की है कि धार्मिक आयोजनों और मेलों में भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

बसपा जिलाध्यक्ष ने कोलारस एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

खाद की कालाबाजारी और अवैध शराब पर कार्रवाई की मांग

शिवपुरी, देशबन्धु। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुआलाल जाटव ने जिले की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने किसानों, ग्रामीणों एवं आमजन से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है।

ज्ञापन में बसपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर खाद की कालाबाजारी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि खाद वितरण व्यवस्था की जांच कर किसानों को उचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए तथा अवैध तरीके से खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा भी उठाया गया। बसपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अवैध शराब के कारण सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और इस पर प्रभावी रोक लगाई जाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों से ऐसे स्थानों की जांच कर अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में अन्य स्थानीय समस्याओं का भी उल्लेख करते हुए कहा गया कि आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

रावत समाज युवा संगठन ने आयोजित किया प्रतिभा सम्मान समारोह

मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित, 2 छात्रों को दिए लैपटॉप

शिवपुरी, देशबन्धु। जिला शिवपुरी रावत समाज युवा संगठन के तत्वावधान में समाज के होनहार और प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रंग-बिरंगे टेंट और आकर्षक मंच से सजे इस विशाल पाण्डाल में समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं और मातृशक्ति ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों के स्वागत और समाज के आराध्य देव के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और युवा संगठन के पदाधिकारियों ने मंच साझा किया। कार्यक्रम के दौरान आधुनिकता और भव्यता का विशेष ध्यान रखा गया। मंच के केंद्र में लगी एक विशाल एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रत्येक प्रतिभा के सम्मान के क्षण को उपस्थित जनसमुदाय को लाइव दिखाया गया। समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उनकी

उत्कृष्ट शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए मुख्य अतिथियों द्वारा अत रावत युवा संगठन द्वारा टॉपर दो छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए गए स्मृति चिह्न (शील्ड) और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही किसी भी समाज के विकास की धुरी है। आज के इस दौर में हमारे समाज के युवाओं ने शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सेवाओं में नए आयाम स्थापित किए हैं। युवा संगठन का यह प्रयास सराहनीय है क्योंकि ऐसे आयोजनों से न केवल वर्तमान प्रतिभाओं का मान बढ़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिलती है। आयोजन में रावत युवा संगठन के अध्यक्ष (सुरेंद्र सिंह रावत मणिखेड़ा) एवं पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत, संगठन सदस्य प्रमोद रावत, लालगढ़ हरदीप रावत, ब्रज रावत धर्मेंद्र रावत, मुड़री नरोत्तम रावत, छोटू रावत, खेरोना, ओम रावत, रणबीर रावत, दीपक रावत, सतीश रावत, केदार रावत, लक्ष्मण रावत, जलवासा यशवंत रावत, अशोक रावत सहित युवा संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश का स्वर्णिम प्रदर्शन

39 पदकों के साथ बना ओवरऑल चैंपियन

प्रदेश की बेटियों ने भी दिखाया दमखम

भोपाल, देशबन्धु। मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने रायपुर (छत्तीसगढ़) में 12 से 14 जून 2026 तक आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब-जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 39 पदक अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, सब-जूनियर बालक एवं सब-जूनियर बालिका वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट

प्रदर्शन ने एक बार फिर मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय जलक्रीड़ा मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाया। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश ने कुल 39 पदक अर्जित किए, जिनमें 25 स्वर्ण, 11 रजत एवं 3 कांस्य पदक शामिल हैं। जूनियर वर्ग की 1000 मीटर एवं 500 मीटर स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने 24 पदक जीते, जिनमें 16 स्वर्ण, 6 रजत एवं 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं सब-जूनियर वर्ग की 500 मीटर एवं 200 मीटर स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने 15 पदक अर्जित किए, जिनमें 9 स्वर्ण, 5 रजत एवं 1 कांस्य पदक शामिल है। देवास जिले के खातेगांव की प्रतिभावान खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया। खिलाड़ी माही साहू ने जूनियर वर्ग की 500 मीटर सी-4 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया। दिव्यानी जाट ने सी-2 500 मीटर एवं सी-4 1000 मीटर स्पर्धाओं में दो रजत पदक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं भाग्यश्री साहू ने के-4 200 मीटर स्पर्धा में रजत पदक तथा के-2 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश के पदक खाते में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई उपलब्धियां अर्जित कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। यह उपलब्धि मध्यप्रदेश की खेल अकादमियों में उपलब्ध वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं एवं सुनियोजित प्रतिभा विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। साथ ही खातेगांव की बेटियों सहित प्रदेश के खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है तथा मध्यप्रदेश को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान प्रदान कर रहा है।

इजरायल ने अमेरिका-ईरान समझौते का किया कड़ा विरोध, कहा

राष्ट्रपति ट्रंप की किसी भी डील से बंधा नहीं है इजरायल

तेल अवीव, (एजेंसियां)। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का इजरायल ने कड़ा विरोध किया है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के समझौते में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल है। ऐसे में इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेनग्विर ने कहा कि इजरायल किसी के डील से बंधा हुआ नहीं है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि ट्रंप का एग्रीमेंट हमें बांधता नहीं है। इजरायल अमेरिका के अंदर नहीं है और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हमारा कर्तव्य इजरायल के नागरिकों, आईडीएफ के सैनिकों और यहूदी लोगों के प्रति है और हजारों साल के देश निकाला के दौरान सताए गए और मारे गए यहूदियों के प्रति हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है कि हम इजरायल की जमीन पर यहूदियों को

सुरक्षा दें। उन्होंने कहा कि हर बार जब हम इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुके, तो हमने खून की कीमत ब्याज के साथ चुकाई। यह ओस्लो समझौते में सच था, यह 2006 में लेबनान समझौते में सच था और यह गाजा में हर उस समय सच था जब हमारी मुश्किलें बढ़ीं। हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। फिर भी, इजरायल कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं है। बता दें, बनाना रिपब्लिक का मतलब ऐसे देश से होता है जिसकी नीतियां या फैसले बाहरी शक्तियों के प्रभाव में हों और जो पूरी तरह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम न हो। इजरायली मंत्री ने कहा, 'मैं ये बातें प्रधानमंत्री से हर समय कहता हूं कि ऐतिहासिक क्षणों में, ऐतिहासिक फैसला लिया जाना चाहिए। हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, और यह हमें किसी भी तरह से बांधता नहीं है। हमें हिज्बुल्लाह को खत्म करने से कम किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे किसी भी इलाके से पीछे नहीं हटना चाहिए जिस पर हमारे लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्थिति में वापस नहीं जाना चाहिए जहां हजारों आतंकवादी उत्तरी बस्तियों की घेराबंदी करके बैठे हों और निश्चित रूप से हमें इजरायल पर हो रही फायरिंग के सामने एक पल के लिए भी चुप नहीं रहना चाहिए। लेबनान से इजरायल की तरफ ड्रोन, यूएवी, या मिसाइल के हर लॉन्च से दहिया में इजरायली हमला होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष

राजनीति सत्ता की नहीं, सेवा का माध्यम बनीं

राजेन्द्र शुक्ल

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ क्षण ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के संकल्प, सेवा और सुशासन की विजय है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च माध्यम बनीं। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। आज विश्व भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति, विश्वसनीय

साझेदार और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हुई है और यह परिवर्तन की दूरदर्शी सोच तथा निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है।

प्रधानमंत्री मोदी का देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना किसी पद या प्रचार से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, पारदर्शिता, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की कार्यशैली से अर्जित होता है। उन्होंनें स्वयं को सदैव प्रधानसेवक के रूप में प्रस्तुत किया और गरीब, किसान, महिला, युवा तथा समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सतत प्रयास किया। यही कारण है कि देश की जनता ने बार-बार उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, अथक कार्यशक्ति, दूरदर्शी सोच और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट संकल्प करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, आधारभूत संरचना, रक्षा क्षमता, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों ने करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। शासन की योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी ढंग से पहुँची हैं।

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री श्री मोदी का विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का निरंतर लाभ प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का लाभ निरंतर प्राप्त करता रहा है। प्रदेश में सड़क, रेल, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश एवं परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली अनेक योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के प्रत्येक जिले तक पहुँचा है। विंध्य क्षेत्र और विशेष रूप से मेरा गृहक्षेत्र रीवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का साक्षी बना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ने न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के उस विजन का प्रतीक है जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलते हैं। आज रीवा देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विंध्य की पहचान नई संभावनाओं से जुड़ चुकी है। विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क, रेल सुविधाओं, शिक्षा संस्थानों और आधारभूत संरचना के विस्तार ने विकास के नए द्वार खोले हैं। यह क्षेत्र अब पिछड़ेपन की पहचान से आगे बढ़कर प्रगति और संभावनाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे यह अनुभव करने का अवसर मिला है कि प्रधानमंत्री की सोच केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ भारत के व्यापक निर्माण की है। आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना ने गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व हमें यह विश्वास देता है कि विकसित भारत का संकल्प केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साकार होती राष्ट्रीय यात्रा है। उनके नेतृत्व में भारत ने आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ कह सकता है कि उसका देश विश्व पटल पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे युगनिर्माता नेतृत्व के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

(लेखक मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं)

एम्स भोपाल में चिकित्सा का चमत्कार

किशोर की टेढ़ी रीढ़ की हड्डी का किया ऑपरेशन

भोपाल,देशबन्धु। एम्स भोपाल के चिकित्सकों ने रोबोटिक तकनीक की मदद से एक किशोर की रीढ़ की गंभीर विकृति (स्कोलियोसिस) का सफल इलाज किया। जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब वह सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।

एम्स भोपाल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय किशोर लम्बे समय से रीढ़ की हड्डी के असहनीय दर्द के चलते शरीर के संतुलन में आने वाली समस्या से परेशान था। उसने पहले कई अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने एम्स भोपाल में संपर्क किया। यहाँ अस्थिरोग विभाग के विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच के बाद पाया कि किशोर स्कोलियोसिस नामक बीमारी से ग्रसित है। लिहाजा रोबोटिक तकनीक की सहायता से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया।

अस्थिरोग विभाग के डॉ. पंकज कुमार मिश्रा और डॉ. तेजा का दल ने ऑपरेशन के दौरान अत्याधुनिक न्यूरोमॉनिटरिंग तकनीक का उपयोग किया। इस तकनीक से ऑपरेशन के दौरान नसों की लगातार निगरानी की जाती है, जिससे ऑपरेशन अधिक सुरक्षित और सटीक बनता है तथा जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है। चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक रीढ़ की विकृति को ठीक किया और अब मरीज की स्थिति में अच्छा सुधार देखा गया। इस पूरी प्रक्रिया में एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. प्रणिता मंडल और उनके दल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। खास बात यह रही कि यह ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया। इससे मरीज और उसके परिवार को महंगे इलाज का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा।

अस्थिरोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. रेहान-उल-हक के अनुसार स्कोलियोसिस ऐसी बीमारी है, जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहने के बजाय एक तरफ मुड़ जाती है। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, कंधे और कमर की बनावट प्रभावित होती है तथा आगे चलकर कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि रोबोटिक तकनीक और न्यूरोमॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं जटिल ऑपरेशन को अधिक सुरक्षित बनाती हैं और मरीजों को बेहतर परिणाम देती हैं।

इनका कहना है

संस्थान का उद्देश्य आम लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब जटिल बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े महानगरों का रुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी उन्नत सुविधाएं एम्स भोपाल में उपलब्ध हैं।

- प्रो. डॉ. माधवानन्द कर,
कार्यपालक निदेशक, एम्स भोपाल

बीएमएचआरसी में योग सप्ताह का शुभारंभ

भोपाल,देशबन्धु। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। योग सप्ताह के प्रथम दिन संस्थान के सुरक्षा कर्मियों को योग अभ्यास से परिचित कराया गया तथा योग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। योग प्रशिक्षक सुशील सिंह द्वारा सुरक्षा कर्मियों को विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया और उन्हें योग के महत्व, नियमित अभ्यास से होने वाले स्वास्थ्य लाभ तथा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने में योग की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।। उन्हें बताया गया कि नियमित योग अभ्यास तनाव प्रबंधन, एकाग्रता बढ़ाने तथा कार्यक्षमता में सुधार लाने में सहायक होता है। विशेष रूप से सुरक्षा कर्मियों जैसे दायित्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए योग शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है।

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन

पद वृद्धि के लिए अर्द्धनग्न होकर निकाली दंडवत यात्रा

भोपाल,देशबन्धु। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग-2 (माध्यमिक शिक्षक) और वर्ग-3 (प्राथमिक शिक्षक) के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पद वृद्धि की मांग को लेकर राजधानी में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न होकर दंडवत यात्रा निकाली और सरकार से रिक्त पदों के अनुरूप भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

शिक्षक भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों ने एमपी नगर स्थित जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) तक दंडवत करते हुए मार्च निकाला। इस दौरान महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और पदवृद्धि की मांग की। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक में 25 हजार पद बढ़ाने और माध्यमिक शिक्षक में प्रत्येक विषय में तीन-तीन हजार अतिरिक्त पद सृजित करने की मांग की है। दोपहर डेढ़ बजे वर्षा के दौरान भीगते हुए कई अभ्यर्थी सड़क पर लेटकर भी विरोध दर्ज कराते नजर आए। इसके बाद आयुक्त अभिषेक सिंह ने दो प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि रिक्त पदों की गणना कराएंगे और फिर पदवृद्धि करने पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द पद वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा।

9 महीनों से जारी है आंदोलन

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले नौ महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश में शिक्षकों के डेढ़ लाख से अधिक पद रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग एक लाख और जनजातीय कार्य के स्कूलों में करीब 50 हजार पद खाली हैं। वहीं हजारों उम्मीदवार पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद रोजगार से वंचित हैं।

पुराने रिश्तों की आड़ में धोखा

ट्रेवल एजेंसी से किराये पर लीं 20 टैक्सियां और किसानों को बेच डालीं

भोपाल,देशबन्धु। राजधानी में पुराने रिश्तों की आड़ में किराये पर ली गई टैक्सियों को अवैध रूप से बेचने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंसी संचालक की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक जालसाज ने किराये पर ली गई 20 से अधिक कारों को फर्जी दस्तावेज और अनुबंध तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा अन्य लोगों को बेच दिया।

पुलिस के अनुसार अरेरा हिल्स क्षेत्र निवासी गौरव कुशवाहा ट्रैवल एजेंसी संचालित करते हैं और किराये पर वाहन उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया किशैलेंद्र जोशी नामक व्यक्ति लंबे समय से उनकी एजेंसी से टैक्सियां किराये पर ले रहा था। पुराने व्यावसायिक संबंधों के चलते उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन शैलेंद्र जोशी ने टैक्सी संचालन के बजाय किराये पर ली गई कारों को बेचने का नेटवर्क तैयार कर लिया। उसने अपने सहयोगियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और अन्य लोगों को कम कीमत में वाहन दिलाने का लालच दिया। इसके लिए फर्जी अनुबंध और दस्तावेज तैयार किए गए तथा आर्थिक परेशानी और जरूरत का हवाला देकर सौदे कराए गए। जब तय समय पर वाहन एजेंसी को वापस नहीं मिले और उनकी तलाश शुरू की गई, तब पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अरेरा हिल्स पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र जोशी और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि कई वाहन अलग-अलग लोगों को बेचे जा चुके हैं। पुलिस बेची गई कारों का पता लगाने के साथ पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

कपड़ा कंपनी के संचालक से साढ़े 19 लाख की धोखाधड़ी

भोपाल,देशबन्धु। राजधानी के एक कपड़ा कंपनी के संचालक से करीब 19 लाख 58 हजार रूपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिकंदराबाद निवासी एक कपड़ा एजेंट और उसके पुत्र ने व्यापार के लिए भेजा गया कपड़ा बाजार में बेच दिया, लेकिन उसकी राशि कारोबारी को नहीं लौटाई। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार लखेरापुरा निवासी 64 वर्षीय प्रदीप अग्रवाल एक कपड़ा कंपनी के संचालक हैं। उन्होंने व्यापार विस्तार के लिए सिकंदराबाद निवासी विनोद जैन और उसके पुत्र रवि जैन को कपड़े की बिक्री के लिए एजेंट नियुक्त किया था। उक्त एजेंटों के कहने पर वर्ष 2019 से 2020 के बीच विभिन्न व्यापारियों के लिए 53 बिलों के माध्यम से 21 लाख रुपए से अधिक मूल्य का कपड़ा भेजा गया था। लेकिन भेजे गए माल के एवज में कंपनी संचालक को केवल 6 लाख 10 हजार रूपए का भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि ब्याज सहित 19 लाख 58 हजार रूपए की राशि बकाया रह गई। जब कारोबारी ने संबंधित व्यापारियों से संपर्क किया तो कई मामलों में एजेंटों द्वारा भुगतान पहले ही लेने की जानकारी मिली, जबकि कुछ व्यापारियों ने माल प्राप्त करने से ही इनकार कर दिया। कंपनी संचालक द्वारा एजेंटों से कई बार भुगतान मांगने के बावजूद उन्होंने रकम वापस नहीं की तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस द्वारा कंपनी संचालक की शिकायत की जांच में सामने आया कि उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट से भेजा गया कपड़ा आरोपियों ने प्राप्त कर उसे बेच दिया था।जांच में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की पुष्टि होने पर पुलिस ने विनोद जैन, रवि जैन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

कक्षा पांचवीं और आठवीं की पुन: परीक्षा आज से

प्रदेश में 2,795 परीक्षा केन्द्र बनाए, केन्द्र पर ही मुद्रित होंगे प्रश्नपत्र

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा पांचवीं और आठवीं की पुन: परीक्षा 16 जून से प्रारंभ हो रही है। यह परीक्षा 23 जून तक चलेगी। पुन: परीक्षा में मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदेशभर में 2,795 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

राज्य शिक्षा केन्द्र के अनुसार प्रदेश की सभी शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं तथा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए पुन: परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से आयोजित होगी। कक्षा पांचवीं की पुन: परीक्षा में 1 लाख 17 हजार से अधिक तथा कक्षा आठवीं की परीक्षा में 1 लाख 32 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे।

प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस बार प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र पर ही मुद्रित किए जाएंगे। केन्द्राध्यक्ष परीक्षा पोर्टल से प्रश्नपत्र प्राप्त कर उनका मुद्रण कराएंगे। इस व्यवस्था के लिए जिला परियोजना समन्वयकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के तहत कम से कम दो संगणक अथवा चलित संगणक, दो कार्यशील मुद्रक, अंतरजाल सुविधा(इंटरनेट), पर्याप्त कागज, मुद्रण सामग्री तथा निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

पुन: परीक्षा के लिए जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। जिन केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है, वहां राज्य शिक्षा केन्द्र की अनुमति से अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। पुन: परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उन्हें परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रमुखों और शिक्षकों को सौंपी गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिलों को परीक्षा के निष्पक्ष और व्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं।

पल्स पोलियो के लिए ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

भोपाल,देशबन्धु। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून तक संचालित किए जाने के लिए ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक सिविल डिस्पेंसरी कमला नगर में अनुविभागीय दंडाधिकारी डॉ. अर्चना रावत शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अनुविभागीय चिकित्सा अधिकारी टीटी नगर सर्कल डॉ. अनिमेष सिंह द्वारा पल्स पोलियो अभियान की कार्य योजना की विस्तृत जानकारी देते हु? बताया की टीटी नगर सर्कल में अभियान संचालन हेतु लगभग 57 हजार 633 घर चिन्हित कर 29 हजार 349 बच्चों का पोलियो की खुराक पिलाने हेतु लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए बी टाइप की 147 एवं सी टाइप की 84 टीमों सहित कुल 258 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही 5 ट्रांजिट टीम एवम 02 मोबाइल टीम बनाकर सर्किल में आने वाले व्यस्त चौक चौराह, न्यू मार्केट एवं अन्य आवागमन स्थल पर पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी। इन 288 टीमों की निगरानी हेतु 27 सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के दौरान महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबड़ी, नगर निगम एवं स्कूल शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।

खरीफ सीजन को लेकर आयोजित बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त बोले-

कार्ययोजना करें तैयार, नवाचार को मिलेगी प्राथमिकता

भोपाल,देशबन्धु। खरीफ सीजन को लेकर नर्मदा भवन में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की बैठक हुई। इसमें कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल ने कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की सफलता केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, वैज्ञानिक भंडारण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

दोनों संभाग के जिलों की बैठक में रबी वर्ष 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा भी हुई। इसमें कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त श्री बर्णवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं अन्य संबद्ध विभाग समन्वित एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए किसानों की आय में स्थायी वृद्धि तय करें। वहीं, प्रत्येक जिले की भौगोलिक, जलवायु एवं बाजार आधारित विशेषताओं के अनुरूप दीर्घकालिक कृषि विकास रणनीति तैयार करें।

श्री बर्णवाल ने कहा कि उद्यानिकी का कृषि उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बदलती बाजार परिस्थितियों में नई पीढ़ी के प्रगतिशील कृषक उच्च मूल्य वाली फसलों, औषधीय पौधों, पुष्पोत्पादन तथा व्यावसायिक उद्यानिकी की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सूक्ष्म नियोजन, क्लस्टर आधारित विकास और बाजारोन्मुख उत्पादन प्रणाली विकसित की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव पशुपालन उमाकांत उमराव, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास निशांत वरवड़े, सचिव उद्यानिकी जॉन किंग्सले, भोपाल संभाग आयुक्त संजीव सिंह, नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्रीकांत बनोठ, सचिव मत्स्य विभाग स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक कृषि उमाशंकर भार्गव, संचालक मत्स्य विभाग मनोज पथरोलिया, संचालक मत्स्य महासंघ अनुराग चौधरी सहित दोनों संभाग के सभी जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी मौजूद रहे।

नवाचारों की जानकारी प्रस्तुत

कृषि उत्पादन आयुक्त ने खेतों में नरवाई जलाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने एवं जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से इनके उपयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कहीं। बैठक में मखाना उत्पादन, नदी तटीय क्षेत्रों में तरबूज एवं खरबूज की खेती, टमाटर, औषधीय फसलों एवं व्यावसायिक पुष्प उत्पादन जैसे नवाचारों की जानकारी प्रस्तुत की गई। उद्यानिकी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए शेड नेट हाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चैंबर, कोल्ड चेन, अनुदान आधारित रेफ्रिजरेटेड वाहनों और अन्य पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया। स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देकर कटाई उपरांत होने वाली क्षति कम करने तथा किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

क्रमांक /512069 /2026/ राजस्व / भो.वि.प्रा /26 भोपाल दिनांक: 12.06.2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की इन्द्रपुरी की सेक्टर ए शहीद भगत सिंह मार्केट योजना में स्थित दुकान क्रं.1 सी श्री संतराम दास लालवानी आ. श्री नारुमल के नाम पर मासिक किराये पर आवंटत है। आवंटी श्री संतराम दास लालवानी स्वर्गवास दि. 10.11.2022 को हो जाने के कारण उनके वारिस पुत्र श्री राजेश कुमार लालवानी आ.स्व. श्री संतराम दास द्वारा आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र,शपथ पत्र, एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त दुकान का नामांतरण अपने नाम पर चाहा गया है।

यदि उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/ दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति / दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा / आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड IREL (India) Limited
Formerly Indian Rare Earths Limited.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)
CIN: U15100MH1950GOI008187 Website: www.irel.co.in
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 & ISO 45001: 2018 Company

संदर्भ - विज्ञा 26-27/5 निविदा नोटिस दि. 10.06.2026 /
Ref: ADVT .NO.26-27/5 TENDER NOTICE Date: 10.06.2026
IREL (India) Limited, Chavara invites Bid for the following items/job descriptions.

कार्य नं/Event No. (GeM)	काम/मद विवरण / Job / Item Description
GEM/2026 B/7645202	Excavation, heaping, stacking loading & transportation of mineral sand from Karithura/ Neendakara area to HUP yard at Chavara plant on zero moisture basis - For 120000 Tonne Mechanical loading, transportation & levelling of tails sand from HUP/MSP tails yard to excavated pits at Karithura/Neendakara mining sites on zero moisture basis - For 25000 Tonne

बिड्डर निविदा फार्म http://irel.co.in or http://gem.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। निविदा में कोई शुद्धिपत्र / विस्तार वेबसाइट में ही डाल सकते है।
Bidder may download tender document from http://irel.co.in or http://gem.gov.in website. Any corrigendum / extension to above tenders shall be hosted in above websites only.

CBC 48139/12/0006/2627 ह. प्रधान, चवरा / Sd/- Head, Chavara

नकदी और ईयरफोन छीना, 2 गिरफ्तार

स्मार्ट सिटी पार्क में छात्र को लूटा

भोपाल,देशबन्धु। श्यामला हिल्स थाना अंतर्गत अतिसुरक्षित क्षेत्र में स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में बैठे एक छात्र के साथ दो बदमाशों ने चाकू अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले छात्र के साथ मारपीट की, फिर उसकी जेब से नकदी और ईयरफोन छीन लिया। इसके बाद फोन-पे के जरिए भी रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

श्यामला हिल्स थाना प्रभारी नीलम पटवा के मुताबिक 23 वर्षीय दीपू यादव एक निजी कॉलेज का छात्र है। वह रविवार रात अपनी कॉलेज दोस्त के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में बैठा हुआ था। इसी दौरान दो युवक हाथ में चाकू लेकर वहां पहुंचे। खतरा देखते हुए, छात्र ने अपनी दोस्त को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने छात्र को घेर लिया और चाकू की नोक पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसकी जेब में रखे करीब 2 हजार रुपए, ईयरफोन छीन लिए। इतना ही नहीं, धमकाकर छात्र के मोबाइल से फोन-पे के माध्यम से करीब 12 सौ रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। वारदात के बाद छात्र थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान कृष्णा और रितिक के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उनसे अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

मानसून से पहले जर्जर भवनों पर कार्रवाई शुरू

ननि ने ढहाए 40 साल पुराने आवास

भोपाल,देशबन्धु। मानसून से पहले नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को गौतम नगर स्थित पाठ्य पुस्तक निगम के करीब 40 साल पुराने जर्जर आवास को ढहा दिया गया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इन भवनों को जून 2025 में खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सभी क्वार्टर खाली करा लिए गए थे। लंबे समय से खाली पड़े इन भवनों को बारिश के दौरान संभावित हादसे की आशंका को देखते हुए हटाया गया है। निगम के अनुसार, शहर में वर्तमान में 2275 मकान जर्जर और अति जर्जर स्थिति में हैं, जो बारिश के दौरान कभी भी ढह सकते हैं। इनमें से अब तक तीन मकानों को निगम द्वारा गिराया जा चुका है, जबकि एक मकान मालिक ने स्वयं अपना भवन ढहा दिया। इसके बाद अब 2271 मकानों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। निगम इन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में जुटा है। जर्जर मकानों में सबसे अधिक हाउसिंग बोर्ड के हैं।

पुराने सर्वे के भरोसे निगम

हैरानी की बात यह है कि शहर में जर्जर भवनों का नया सर्वे पिछले तीन वर्षों से नहीं हुआ है। नगर निगम अभी भी वर्ष 2022 के सर्वे के आधार पर ही जर्जर भवनों की सूची तैयार कर रहा है। बरसात से पहले नया सर्वे होना था, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा स्तर पर सहायक यंत्री जर्जर भवनों की सूची अपडेट कर रहे हैं।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
Tele Phone No-07723-224985 Email ID-nppmahasamund@gmail.com

क्र./644 /न.पा./जल.वि./2026-27 महासमुन्द दिनांक 15/06/2026

जेम पोर्टल बिड आमंत्रण सूचना

नगरपालिका परिषद् महासमुन्द के अधीन शासन के जेम पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्लेसमेन्ट (ठेका पद्धिति) के माध्यम से नगर पालिका परिषद महासमुन्द हेतु उच्च कुशल, कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिको को उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	बिड संख्या	कार्य - विवरण	अनु. लागत राशि	अमानत राशि	बिड की अंतिम तिथि
1	GEM/2026/B /766/7665393 Date 15.06.2026	Manpower Outsourcing services Minimum wage Unskilled: Not Required: othrs, Manpower Outsourcing Not required others Manpower services - Minimum wage-Semi-skilled: outsourcing Services Minimum wage Skille& High School others Manpower outsourcing Services Minimum wage Highly Skilled graduate Admin Manpower Outsourcing services Minimum wage Highly skilled High school others.	28861020.00	144305.00	06.07.2026

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते एवं जानकारी कार्यालयीन अवधि मे कार्यालय से एवं शासन के अधिकृत जेम पोर्टल के वेब साईट पर देखी जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद महासुंद

भोपाल, मंगलवार 16 जून 2026

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

लोकतांत्रिक गिरावट की पराकाष्ठा

वैसे तो 2014 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लगातार गर्त में ले जा रही है, परन्तु पश्चिम बंगाल में वहां की सत्ता से हट गयी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को रातों-रात तोड़कर उसका जो हश्र किया गया है, वह शायद गिरावट का सबसे निचला स्तर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अनेक ऐसे कारनामे किये गये हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी किसी सरकार के लिये बहुत शर्मनाक है।

इस बात का लम्बा हिसाब लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार में आने के बाद अपनी जांच एजेंसियों, अलग-अलग ढंग से जुटाये गये पैसों और बेहिचक गैर-लोकतांत्रिक तरीके अपनाते हुए भाजपा ने कई राज्यों में गैरभाजपा सरकारों में तोड़-फोड़ की, अनैतिक तरीकों से केन्द्र के अधीन मौजूद ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया है।

वैसे तो प. बंगाल में भाजपा बड़े अंतर से न केवल जीती वरन सरकार बनाने के लिये उसके पास साफ बहुमत भी उपलब्ध हो गया है। ऐसे में सवाल हो सकता है कि इसके बावजूद टीएमसी को संसद में तोड़ने की ज़रूरत है? यह अन्य दलों को साफ संकेत है कि आगे जाकर उनका भी यही हश्र होगा। इसे अगले वर्ष होने जा रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से भी जोड़ा जा रहा है।

यह भी साफ हो गया है कि भाजपा अब न केवल विपक्षी दलों को तोड़ेगी वरन हर पार्टी के कथित बागी उम्मीदवारों को निर्दिष्ट भी करेगी कि उन्हें फिलहाल किस दल में शामिल होना है। अब तक तो यही होता आया है कि अपनी पार्टी को किसी भय या लालच के चलते छोड़ने वाले विधायक या सांसद सीधे भाजपा का रुख करते थे। चाणक्यगिरी का सम्भवत: यह नवाचार है कि टीएमसी के बागी 19-20 सांसदों को कुछ वक्त पहले हावड़ा में बनी और त्रिपुरा में चुनाव लड़ने वाली नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने के लिये कहा गया। इस घटनाक्रम से एनसीपीआई का नाम लोग जान पाये हैं। राज्य में वह भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का घटक दल है। हालांकि इसकी संस्थापक अध्यक्ष शिवली कुंडू और संगठन सचिव शांतनु डे का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के जरिये मिली। वैसे शिवली का कहना है कि काफी अरसा पहले वे इस पद को छोड़ चुकी हैं तथा अब उसका अध्यक्ष कौन है- वे नहीं जानतीं। हालांकि शांतनु ने टीएमसी से आने वाले बागी सदस्यों का अपनी पार्टी में स्वागत किया है।

अगर एनसीपीआई की राजनीतिक ताकत की बात करें तो इस दल के केवल दो सदस्यों ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी की थी। दोनों को मिलाकर कुल 822 वोट मिले थे। स्वाभाविकत: उसके किसी भी सदस्य को विधानसभा में प्रवेश नहीं मिला था। दोनों की जमानत जब्त हो गयी थी। कल्पना कीजिये भारतीय लोकतंत्र की विद्रूपता का जहां ऐसी पार्टी के 19-20 लोकसभा सदस्य हैं जिसे कुल प्राप्त मतों की संख्या तिहाई में सिमटी हुई है। जैसा अक्सर कहा जाता है कि किसी पार्टी को छप्पर फाड़ पैसे या वोट मिलते हैं, एनसीपीआई के बारे में कहा जा सकता है कि उसे छप्पर फाड़ सांसद मिले हैं। शायद अपनी राजनीति के बल पर उसे यह उपलब्धि कभी हासिल नहीं हो सकती थी। बस, यही वह 'चाणक्यगिरी' है जो देश के लोकतंत्र को मटियामेट कर रहा है।

टीएमसी के सदस्यों पर गाज गिरेगी- यह तो पहले से ही तय था। इन ज्यादातर सांसदों में बेहद तेज्-तर्रार लोग हैं जिनके पिछले एक या दो कार्यकाल बेहद उपयोगी रहे हैं। वे न सिर्फ जनता की आवाज उठाते थे, बल्कि वे सशक्त प्रतिरोध के सच्चे प्रतिनिधि लगते थे। विपक्षी दलों की कम संख्या के बावजूद टीएमसी के कई सदस्यों की ओर पूरा देश आशा भरी निगाहों से देखा करता था। ममता के खुद का विधानसभा चुनाव हारने के बाद यह तक कहा जाने लगा था कि सायोनी घोष पार्टी की भावी नेता हैं। उनसे उम्मीद थी कि ममता की तरह न केवल उनकी आक्रामकता बरकरार रहेगी बल्कि वे टीएमसी की धार को और चमकाएंगी।

मजेदार यह है कि जिस धर्मनिरपेक्ष चरित्र व विश्वासों के चलते ममता ने तीन मुस्लिमों को सांसद बनाया था, वे भी एनसीपीआई का दामन थाम चुके हैं। इन सभी लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली जाकर न केवल खुद को टीएमसी से अलग होने की घोषणा की, वरन सदन में अलग बैठने की भी मांग की है। कहना न होगा कि ऐसे मामलों में बिरला वही फैसला करते हैं जो भाजपा के अनुकूल होते हैं। एक-दो दिनों में शायद इसकी विधिवत घोषणा भी हो जाये- मोदी-शाह की मंशा व निर्देशों के अनुकूल।

टीएमसी के थोड़े-बहुत बचे हुए लोगों को डराने के लिये प.बंगाल की नयी भाजपा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनावी नतीजों की रात को टीएमसी, कांग्रेस व साम्यवादी दलों के दफ्तरों को जलाया गया, सांसदों के घरों में जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है, फाल्टा से हारने वाले जहांगीर खान को पुलिस उनके क्षेत्र में सरेआम परेड करा रही है तो ये बचे-खुचों को एनसीपीआई में शामिल होने का संदेश है।

भाजपा जो करेगी वह करेगी ही, इंडिया गठबन्धन से न जुड़ने अथवा मिल-जुलकर चुनाव न लड़ने का भारी खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ा है। यह संदेश सभी विपक्षी दलों के लिये है।

जिबह किया जाता जनतंत्र!

अपनी बंगाल फतेह को विधानसभा से आगे ले जाने और वास्तव में सीधे लोकसभा फतेह तक पहुंचाने में, मोदीशाही को जरा भी देर नहीं लगी है। 4 मई को विधानसभा चुनाव में बंगाल में उसकी जीत का ऐलान हुआ और इसके मुश्किल से एक महीना दस दिन बाद, 14 जून को काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा ग्रुप के बागी सदस्यों ने, स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की और बागी गुट के उन्नीस-बीस सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन देकर, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ग्रुप से अलग बैठाए जाने की मांग की।

पर तृणमूल कांग्रेस के ममता वफादार गुट द्वारा इससे पहले ही स्पीकर से मुलाकात कर, उन्हें याद दिलाया जा चुका था कि दल-बदलविरोधी कानून के अनुसार और खासतौर पर शिव सेना के विभाजन के प्रकरण में 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सीमित निर्णय के अनुसार, तृणमूल के बागी गुट को लोकसभा में एक अलग गुट के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। कानून के जानकारों के अनुसार, किसी राजनीतिक पार्टी के विधायी दल के दो-तिहाई सदस्यों के अलग होने की सूरत में भी, उन्हें दलबदल-विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता से तभी सुरक्षा मिल सकती है, जब मूल पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय हो रहा हो या उनके विलय से कोई नयी पार्टी बन रही हो। शिव सेना प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि यहां विलय से आशय राजनीतिक पार्टी के विलय से है, न कि विधायी ग्रुप के दो-तिहाई या उससे अधिक के विलय से।

बहरहाल, दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान, बागी तृणमूल सांसदों के कदमों को और सच पूछें तो उनके पीछे आधे प्रकट तथा आधे परोक्ष रूप से काम कर रहे संघी-भाजपायी 'चाणक्यों' के कदमों को नहीं रोक सकते थे, नहीं रोक पाये। बेशक, यह कोई संयोग ही नहीं था कि स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की बागी गुट की कार्यनीति, इस मुलाकात से ठीक पहले हुई केंद्र सरकार के मंत्री, भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक में तैयार की गयी थी। बिड़ला से मुलाकात के बाद, बागी गुट के प्रवक्ताओं ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। पहली, जो कि इस गुट के खड़े किए जाने तथा उसके लिए दो-तिहाई का आंकड़ा जुटाए जाने की कसरत शुरू होने के बाद से ही स्पष्ट थी—यह गुट नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ मजबूत करेगा और इस तरह कथित रूप से अपने चुनाव क्षेत्रों के विकास का रास्ता बनाने के लिए करेगा।

दूसरी घोषणा थी, बागी गुट के एनसीपीआई में विलय के निर्णय की। जाहिर है कि इस गुट द्वारा इस फैसले की जानकारी, लोकसभा स्पीकर को भी दी गयी थी। समझना मुश्किल नहीं था कि इस पैंतरे का मकसद, कम से कम कागजी तौर पर दलबदल-विरोधी कानून की, टूटने वाले गुट के किसी अन्य पार्टी में विलय की शर्त पूरी करना है। काफी खोज-बीन करने पर पता चला कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) तीन-चार साल पहले त्रिपुरा में बनायी गयी, एक गैर-मान्यताप्राप्त किंतु रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर 800 वोट हासिल करने से ज्यादा कोई विधायी अस्तित्व नहीं था। अचानक यह अनाम पार्टी 20 लोकसभा सदस्यों के साथ, चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है।

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कथित विलय ऐसी अनाम पार्टी में ही क्यों, खुद भाजपा में क्यों नहीं? बेशक, एक किस्त में इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं, फिर भी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को भाजपा में मिलाने का खेल, मोदी निजाम के लिए कोई नया नहीं है।

राजेंद्र शर्मा

महिला आरक्षण को लागू करने की आड़ में, परिसीमन लागू करने के इस खेल को, संसद के पिछले सत्र में एकजुट विपक्ष ने शिकस्त दे दी थी। लेकिन, उसके बाद से विपक्ष की न उतनी ताकत रह गयी है और न विपक्ष उतना एकजुट नजर आता है। वास्तव में तृणमूल की टूट और द्रमुक के इंडिया ब्लाक से अलग होने ने ही, संघ-भाजपा में इसकी उम्मीदें जगायी लगती हैं।

विधानसभा चुनावों के हालिया चक्र से जरा सा पहले ही, आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों को, इसी तरह बागी बनवा कर भाजपा में शामिल किया गया था। सात की ही संख्या इसलिए कि राज्यसभा में आप पार्टी के कुल 10 सदस्य थे और 7 सदस्यों से दो-तिहाई की शर्त पूरी हो जाती है। इससे पहले, 2019 के विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में तेलुगू देशम की हार के बाद, उसके चार राज्यसभा सदस्यों का भी इसी तरह से भाजपा में विलय कराया गया था। तब बागी तृणमूल सांसदों का सीधे भाजपा में ही विलय क्यों नहीं, जबकि इतना तो साफ ही है कि इस गुट को, भाजपा के पुछल्ले के रूप में काम करने के लिए ही तोड़ा गया है।

इसके तीन कारण हो सकते हैं, जो सभी एक साथ भी मौजूद हो सकते हैं। पहला यह कि चुनाव आयोग की भांति-भांति की मदद के अलावा, जिस तृणमूल के भ्रष्टाचार से लेकर हिंसा तक के आख्यानों के सहारे, संघ-भाजपा ने चुनावी फतेह हासिल की है, उसके सांसदों और खासतौर पर लोकसभा सदस्यों को थोक के भाव भाजपा में लाकर पचा पाना, संघ-भाजपा के जबर्दस्त हाजमे के लिए भी मुश्किल हो सकता है। हरेक तृणमूल लोकसभा सदस्य, जिस भाजपा उम्मीदवार को हराकर लोकसभा पहुंचा है, उसके साथ एक ही पार्टी में आसानी से तो एडजस्ट नहीं ही हो सकता है। इससे कहीं बेहतर विकल्प यह होगा कि सुरक्षित दूरी रखकर, संघ-भाजपा बाद में छांट-छांटकर अपने लिए विशेष उपयोगी नेताओं को अपने साथ मिला ले और बाकी को कूड़ेदान में जाने दे। दूसरे, संसद में संख्याबल बढ़ाने के अलावा तृणमूल के लोकसभा सदस्यों का जनसमर्थन का दायरा बढ़ाने में अगर कोई उपयोग हो, तो शायद ज्यादा उपयोग उनके भाजपा से सुरक्षित दूरी बनाए रखने में ही हो। और तीसरा यह कि भाजपा को बखूबी पता है कि इस तरह का विलय, राजनीतिक ही नहीं कानूनी तौर पर भी विवादास्पद होगा और उसे अदालतों में चुनौती दिया जाना तय है। ऐसे में वह अपने हाथ मैले क्यों करती, जबकि अपने पाले में करीब बीस सांसद बढ़ाने के सारे लाभ उसे, तृणमूली बागियों के एनसीपीआई सदस्य कहलाने पर भी मिल ही रहे होंगे।

बेशक, तृणमूली बागी सांसद चाहे ओम बिड़ला के फैसले के बाद, अलग गुट के तौर पर मान्यता प्राप्त कर लें या एनसीपीआई के लोकसभा ग्रुप की मान्यता प्राप्त कर लें, ऐसा कोई भी फैसला विवादास्पद होगा और ज्यादा संभावना है कि उसे अदालत में चुनौती भी दी जाए। लेकिन, महाराष्ट्र में पहले शिव सेना तथा उसके बाद एनसीपी के विभाजन के प्रकरण और अभी हाल में आप पार्टी राज्यसभा सदस्यों के भाजपा के विलय को दी गयी चुनौतियों के अनुभव से यह साफ है कि व्यावहारिक रूप से, स्पीकर के फैसले से बनने वाली स्थिति, जल्दी से बदलने वाली नहीं है। मोदीशाही के जरिए जो संघ-भाजपा तंत्र साम-दाम-दंड-भेद के अपने हथियारों से, अपने विरोध में खड़ी पार्टियों का और खासतौर पर उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का इस तरह का विभाजन सुनिश्चित करता है, वही संघ-भाजपा तंत्र पहले ही यह भी सुनिश्चित कर चुका होता है कि उसके लिए फायदे के इस तरह के घटनाक्रम में कोई अन्य संस्था बाधा नहीं डाले। उसे पलटा तो हर्गिज नहीं जाए। जाहिर है कि बारह वर्ष के अनुभव ने उसके इस भरोसे को पुख्ता ही किया है कि जनतंत्र की कोई भी संस्था, उनके मंसूबों के आड़े आने लायक नहीं रही है।

जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के हालिया चक्र के नतीजों से और खासतौर पर बंगाल फतेह करने के बाद से, मोदीशाही के हौसले सातवें आसमान पर हैं। इसीलिए, तृणमूल लोकसभा सांसदों के मामले को, मोदीशाही की अपनी बंगाल की फतेह का संसद का विस्तार करने की मुहिम तक ही सीमित कर के नहीं देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों के अनुसार, तृणमूल सांसदों की बगावत संगठित करने के दौरान ही, संघ-भाजपा के खिलाड़ी महाराष्ट्र में भी विभाजन के पिछले चक्र के जरिए पहले ही बहुत कमजोर किए जा चुके विपक्ष में, विभाजन के एक और चक्र की तैयारियों में जुटे हुए थे। उद्धव ठाकरे की शिव सेना खासतौर पर उनके निशाने पर थी, जिसके अब सिर्फ 9 लोकसभा सदस्य बचे हैं। यह दूसरी बात है कि सारी कोशिशों के बावजूद, संघ-भाजपा के हथियार के तौर पर शिंदे के लिए, छः (यानी दो-तिहाई) बागी जुटाना संभव नहीं हुआ, जो कि दलबदल कानून के चाबुक से बचने के लिए जरूरी संख्या थी।

इसे देखते हुए, हैरानी की बात नहीं होगी कि कई राजनीतिक टीकाकारों का यह अनुमान सच निकले कि मोदीशाही, संसद के मानसून सत्र में दोबारा, महिला आरक्षण सह परिसीमन विधेयक का पैकेज देश के सिर पर थोपने की कोशिश कर सकती है। संसद में अपना संख्या बल बढ़ाने के इस जुनून के पीछे ऐसा ही कोई गहरा मकसद नजर आता है। यह किसी से छुपा नहीं है कि महिला आरक्षण की आड़ लेकर, परिसीमन को आगे बढ़ाने में ही मोदीशाही की असली दिलचस्पी है। और यह इसलिए है कि उसने समझ लिया है कि जनसंख्या अनुपात पर आधारित परिसीमन के जरिए, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अपने गढ़ों का तुलनीय राजनीतिक वजन और बढ़ाने के जरिए ही, वह 2029 के चुनाव में अपनी जीत पक्की कर सकती है। 2024 के चुनाव नतीजों ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया है। इसीलिए, उसे सब कुछ चाहिए। उसे अपनी जेब में चुनाव आयोग भी चाहिए। उसे अपने अनुकूल मतदाता सूची भी चाहिए, जिसमें से उसकी नजरों में 'गैर-भरोसेमंद' मतदाताओं को छांटा जा चुका हो। उसे मतगणना तक मनमानी चाहिए। और इस सब के ऊपर से, ऐसा परिसीमन भी चाहिए, जिसमें 'असहयोगी' दक्षिण को छोटा किया जाए और चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह इलाके छांट-छांटकर बनायी जाएं, जिससे विरोधियों का दायरा छोटे से छोटा हो जाए और उसका दायरा बड़े से बड़ा। परिसीमन का यह संघी मॉडल देश, असम और जम्मू-कश्मीर में देख भी चुका है।

बेशक, महिला आरक्षण को लागू करने की आड़ में, परिसीमन लागू करने के इस खेल को, संसद के पिछले सत्र में एकजुट विपक्ष ने शिकस्त दे दी थी। लेकिन, उसके बाद से विपक्ष की न उतनी ताकत रह गयी है और न विपक्ष उतना एकजुट नजर आता है। वास्तव में तृणमूल की टूट और द्रमुक के इंडिया ब्लाक से अलग होने ने ही, संघ-भाजपा में इसकी उम्मीदें जगायी लगती हैं कि वे एक बार फिर परिसीमन का रास्ता खोल सकते हैं और अगला आम चुनाव अपनी झोली में डाल सकते हैं। लेकिन, ठाकरे की शिव सेना की मुस्तैदी ने और द्रमुक के संघवाद के सिद्धांतों पर समझौता नहीं करने के ऐलान ने, संघ-भाजपा के इस संभावित खेल को विफल करने की शुरूआत भी तो कर दी है।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और विपक्ष की चुनौतियां

■ राजेश पांडेय

भारत में केंद्र और राज्य की सरकारें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती हैं। शहर से लेकर गांवों तक लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव वोट से करते हैं। सभी चुनावों में स्थानीय स्तर पर हेराफेरी की घटनाएं होती हैं। मतदान केंद्रों पर कब्जा, फर्जी वोटिंग, मतगणना में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आते हैं। फिर भी, राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों की शुद्धता और पवित्रता संदेह से परे रहती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सत्ताधारी पार्टी तय कर रही है कि वोटर कौन रहेगा और कौन नहीं। कम से कम मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया से तो यही तस्वीर उभरती है। धांधली के आरोपों, विसंगतियों और खामियों की कहीं सुनवाई नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं से इंसाफ की उम्मीद खत्म होती जा रही है।

स्वस्थ और सच्चे लोकतंत्र की पहली शर्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं। अब इसकी गारंटी नहीं रही। चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों की सूची दिन-ब-दिन लंबी हो रही है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व करते हैं लेकिन हकीकत एकदम अलग है। स्वयंसेवी संगठनों- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और महाराष्ट्र स्थित वोट फॉर डेमोक्रेसी ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कई विसंगतियों का जिक्र किया है। दोनों चुनावों में कुल मतदान और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर पाया गया है। वोटिंग के आंकड़े काफी विलंब से जारी हो रहे हैं। वोटिंग के आखिरी घंटों में वोटरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी चिंताजनक और अविश्वसनीय है। एडीआर ने चुनाव आयोग को कई मौकों पर पत्र लिखकर सभी पहलुओं की ओर उसका ध्यान आकर्षित कराया है। लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं।

देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष को अपना हर मोर्चा दुरुस्त करना होगा। उसे हर राज्य में कड़ी चुनौती पेश करने के हालात बनाना चाहिए। जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगती हैं तो उसे रास्ते पर लाने में विपक्ष दलों की एकजुटता भी अच्छा प्रभाव पैदा कर सकती है। संवैधानिक संस्थाएं सत्ता और उसके अन्य अंगों की असंवैधानिक और गैरकानूनी कार्रवाईयों को रोकने का सबसे प्रभावी औजार हैं।

चुनाव आयोग की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं है। इसका असर हर जगह दिखाई पड़ रहा है। आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी संदेह के दायरे में हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में इसके सबूत मिले हैं। अपेक्षाकृत महत्वहीन चुनाव तक धांधली की चपेट में आ रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी गड़बड़ी करते रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज करने की ताजा घटना इसकी अगली कड़ी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

देश की सर्वोच्च अदालत से अनियमितताओं को रोकने की उम्मीद की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अहम मामलों में क्लीन चिट दे दी है। खासतौर से एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 मई को आए कोर्ट के फैसले में वोटरों के अधिकारों की रक्षा की फिक्र दिखाई नहीं देती है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। अदालत ने यह जरूर माना है कि आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता है। यह केंद्र सरकार का काम है। फिर भी, एसआईआर की जटिलता और खामियों पर उसने गौर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले कुछ राज्यों में हड़बड़ी में कराई गई प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। आयोग को किसी बिंदु पर जवाबदेह नहीं ठहराया है।

अब तक मतदाता सूची में वोटरों का नाम दर्ज करने और हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान रही है। हर साल वोटर लिस्ट का संक्षिप्त संशोधन (समरी रिवीजन) होता है। चुनाव आयोग 18 साल से अधिक आयु के नए वोटरों को शामिल करने के लिए अभियान चलाता है। लेकिन लगता है कि एसआईआर के जरिये नाम शामिल करने के बदले हटाने की मुहिम चलाई गई है। लगातार खबरें आ रही हैं कि सबसे अधिक नाम अल्पसंख्यकों, दलितों के हटाए गए हैं। दरअसल, भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके पास कई जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। इनमें अधिकतर लोग कमजोर और गरीब हैं। भला सोचिए दूरदराज के कस्बों, गांवों में बैठे लोगों के लिए दस्तावेज जुटाना कितना कठिन है। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल कराया है। अनुमान है, 2026 के शुरुआती महीनों में 134 करोड़ लोग आधार का उपयोग कर रहे थे।

चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। उसे सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र वोटर मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित न रह जाए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। एसआईआर के तहत करोड़ों वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करने का अभियान चल रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुमानों में यह संख्या लगभग साढ़े छह करोड़ बताई गई है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल, मई में हुए विधानसभा चुनाव में तार्किक विसंगति जैसे नए मापदंड के तहत 27 लाख वोटरों का मताधिकार छीन लिया गया। तमिलनाडु में 97 लाख लोग बाहर हुए हैं। बिहार में 25 लाख वोटरों को जगह नहीं मिली है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों के राज्य उत्तरप्रदेश में एक करोड़ से अधिक वोटर अधर में हैं। जाहिर है, ये हालात लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हैं।

संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी के कारण चुनावों में मुकाबला बराबरी का नहीं रह गया है। दौड़ शुरू होने से पहले ही सत्ताधारी दल निर्णायक बढ़त की स्थिति में रहने लगा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों के सामने कठिन चुनौतियां हैं। उसके अपने विरोधाभास और मतभेद अलग हैं। कई राज्यों में उनके हित आपस में टकराते हैं। 2023 में बने इंडिया गठबंधन के सदस्य कई मौकों पर अलग दिशाओं में चलते हैं। लेकिन उसने इस वक्त एसआईआर के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 8 जून को हुई उसकी बैठक में आम राय से एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया गया है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर का उपयोग चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि एसआईआर से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसने चुनावों की निष्पक्षता और पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

एसआईआर के बारे में विपक्ष के सवाल जायज हैं। इसके बावजूद एसआईआर को नए सिरे से कानूनी चुनौती देने के नतीजों पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। कानूनी रास्ते तो ठीक हैं पर विपक्ष के लिए मैदानी मोर्चे को संभालना ज्यादा जरूरी है। 8 जून की बैठक में गठबंधन के मतभेद भी सामने आए हैं। सहयोगी दलों ने कहा कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रणनीति ने गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपनी रणनीति पर नए सिरे से गौर करना होगा। तमिलनाडु में वह द्रमुक को छोड़कर एक्टर विजय की पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस के रणनीतिकार इसे भविष्य की नीति मानते हैं। उनकी सोच है कि तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ पार्टियों के प्रभाव क्षेत्र से निकलकर दूसरी दिशा में बढ़ रही है। बंगाल में तृणमूल के साथ उसके मेलजोल की हलचल तेज है। केरल में तो यूडीएफ गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस का वामपंथियों (एलडीएफ) से हितों के टकराव का सीधा मामला है। वहां यूडीएफ और एलडीएफ के बीच हर पांच साल में सत्ता बदलती रही है। केवल 2021 में एलडीएफ ने विजयन के नेतृत्व में पहली बार दोबारा बहुमत हासिल किया था। सीपीएम की आपत्ति कांग्रेस नेताओं खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा विजयन पर व्यक्तिगत प्रहार से संबंधित है। वहां कांग्रेस और वामपंथियों के रास्ते अलग हैं लेकिन चुनाव अभियान में बार-बार निजी हमलों से तो बचा ही जा सकता है। बंगाल में कांग्रेस चुनाव से पहले ही तृणमूल के साथ मिलकर चल सकती थी। इससे एसआईआर के जरिये हुई कथित धांधली से निपटने में कुछ हद तक मदद मिल सकती थी। बंगाल में अब तक कांग्रेस की रणनीति को अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता प्रभावित करते रहे हैं। वे तृणमूल की शीर्ष नेता ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक हैं। कांग्रेस ऐसे नेताओं से अलग हटकर नई वास्तविकताओं के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर सकती है।

अपने ऐतिहासिक अतीत, लंबे समय तक देश पर शासन करने, मौजूदा लोकसभा में 100 सीटों और चार राज्यों में सरकार होने के कारण इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए उसे अपने सहयोगियों की महत्वाकांक्षाओं, जरूरतों और मैदान की स्थिति को देखकर कदम उठाना होंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी के हाथ में विपक्ष की कमान है। लिहाजा, कांग्रेस के लिए सपा के पीछे चलना व्यावहारिक राजनीति होगी। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को सीटों के बंटवारे में वास्तविक स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। वे अपने नफा-नुकसान को परखें लेकिन यह ध्यान रखें कि महत्वाकांक्षा, टकराव और जिद से चुनौती कमजोर न पड़ जाए।

देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विपक्ष को अपना हर मोर्चा दुरुस्त करना होगा। उसे हर राज्य में कड़ी चुनौती पेश करने के हालात बनाना चाहिए। जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगती हैं तो उसे रास्ते पर लाने में विपक्ष दलों की एकजुटता भी अच्छा प्रभाव पैदा कर सकती है। संवैधानिक संस्थाएं सत्ता और उसके अन्य अंगों की असंवैधानिक और गैरकानूनी कार्रवाईयों को रोकने का सबसे प्रभावी औजार हैं। अगर वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करेंगी तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। निश्चय ही यह स्थिति गंभीर और निराशाजनक है। इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। वह अपनी मैदानी सक्रियता से जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को उसके अधिकार हासिल करने में मदद कर सकता है। भारत में मताधिकार हर व्यक्ति को सबके बराबर खड़े होने का अधिकार देता है। हमारे यहां वंचित वर्गों की सबसे बड़ी संपदा और ताकत उसका वोट है। उसके इस अधिकार की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ललित सुरजन की कलम से

तीसरा मोर्चा बनाम वामदल

'1952 में पहले आम चुनाव के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। सवाल उठता है कि जो पार्टी या जो विचारधारा 1952 में कांग्रेस के विकल्प के रूप में मौजूद थी वह उस जगह से अपदस्थ कैसे हुई और उग्रराष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादी शक्तियों ने वामपंथी ताकतों को धीरे-धीरे कर भारतीय राजनीति के हाशिए पर क्यों कर धकेल दिया। यह एक प्रकट वास्तविकता है और इसका सामना करने का साहस वामदलों में होना चाहिए। मेरा मानना है कि आम चुनाव के समय क्षेत्रीय दलों से अल्पकालीन गठजोड़ करने से वामपंथी ताकतें मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर ही होंगी। मेरा यह भी मानना है कि आज के वैश्विक परिदृश्य को समझने की क्षमता भारत में या तो कांग्रेस में है या फिर वामपंथियों में; और अपनी तार्किक क्षमताओं का मैदानी कार्रवाई में रूपांतरण करने से ही वाममोर्चा 1952 में या उससे बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है।'

(देशबन्धु में 16 मई 2013 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/06/blog-post_22.html

पावन प्रसंग

मन:स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले

जिसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया,वह हार गया। परिस्थितियों के विरुद्ध जो लड़ सका, मन:स्थिति उच्च बनाकर, जीवन समर में लड़ सका वही विजेता हुआ। यदि हमारे भीतर अपने जीवन के उद्देश्य को सफल, सार्थक करने की तीव्र अभीप्सा हो तो परिस्थितियां हमारे जीवन की परिभाषा नहीं बन सकती हैं। बात यहां पर मन:स्थिति की है। उत्कृष्ट मन क्या नहीं कर सकता है? आवश्यकता है उसकी शक्ति को पहचानने की तथा उससे उभयपक्षीय निर्माण प्रस्तुत करने की। जब हम परिस्थितियों पर अत्यधिक जोर देते हैं, स्वयं को निर्बल एवं असहाय घोषित कर देते हैं, स्वयं की क्षमताओं से परिचित नहीं होते, तभी इस प्रकार की विसंगति खड़ी होती है कि हमारा अंत:करण हमारा साथ देना बंद कर देता है। मन की ऊर्जा का भरपूर लाभ लेना है तो मन को बहुत महत्व देना छोड़ दीजिए, उसे ऐसा बनाइए ताकि उससे उच्चतर प्रयोजनों में सहायता मिल सके। हमारा मन तभी अपना है, जब उसने किसी उच्च प्रेरणा हेतु अपना समर्पण करना सीख लिया हो।

मन की शक्ति को समझना ही वास्तविक अध्यात्म है एवं इस हेतु हमें अपनी आसक्ति को मिटाना चाहिए। जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए मन का निरासक्त होना आवश्यक है। हम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करें, इससे शुभ कुछ हो नहीं सकता। जब मन पर हमारा आधिपत्य होता है तो यह संभव है कि हम विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी उत्कृष्ट मनोदशा का परिचय दें एवं जीवन को धन्य एवं महान बनाएं। मन की गुलामी से मुक्थि ही साधना का मूल केंद्र है। उसे जिसने समझ लिया, वह फिर परिस्थितियों का ऐसा रोना नहीं रोता है। उसका असीम उत्साह एवं दृढ़ लगन स्वत: आदर्श सत्परिणाम उपस्थित करने की दिशा में बढ़ चलते हैं एवं उसे परिस्थितिवश विवश नहीं होना पड़ता है।

जीवन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सब को याद कर लेना चाहिए कि बिना मन:स्थिति में परिवर्तन किए, बिना स्वयं को सुधारे आप जीवन का महत्वपूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं। अफने का मालिक होने में ही भलाई है,शेष तो आत्मप्रवंचना भर है। इसलिए पहला कार्य है, अपने मन पर संपूर्ण एवं एक पक्षीय नियंत्रण स्थापित करना, उसे एक दैवी वाहन के रूप में प्रयुक्त करना तथा उससे महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करना।

जब मन इस स्तर का बन जाता है, तो ही उससे अनेकानेक अनुदान एवं वरदान प्रस्तुत करना संभव होता है। मन को पूर्णरूपेण समझना ही अध्यात्म है। आज हर जगह परेशानी है, विषय विकार है तथा जीवन की कठिनाई दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है, वह इसीलिए क्योंकि हमने मन की शक्ति को पहचानने एवं उसका सदुपयोग करनी की ठानी नहीं है। मन हमारा बेकारी में पड़ा रहता है, उसे यह बोध नहीं कि वह किस महान तत्व के अनुशीलन से अनभिज्ञ है। सत्य यही है कि जो मन को जीत ले वही भाग्यवान, जो मन से हार जाए वही अपाहिज। वास्तविक वस्तु चेतना है एवं मन उसीसे हेरफेर किया करताहै, उसकेकारणह ी मन प्रयासचला करतेहैं. मनुष्यक ो जीवंत स्वरूपयदिदेखना हो, उसेपहचानने की सामर्थ्य विकसित करनी हो तो इतना करना चाहिए कि मन के मूल में छिपी आसक्ति को पहचाना जाए और उससे दैवी विधान अनुरूप कार्य लेने की क्षमता विकसित की जाए।

-अखंड ज्योति

सार-समाचार

नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना में शेष रहे 26 ग्रामों को परियोजना में शामिल किया जाए

आष्टा, देशबन्धु। क्षेत्र के विकास को लेकर कठिन परिश्रम कर विधानसभा क्षेत्र को अधिक से अधिक विकास योजनाओं का लाभ दिलाने में दिन रात जुटे विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने अपने अभी तक के कार्यकाल में करोड़ो के विकास कार्यो की जो सौगातें दी वे आज धरातल पर दिख रही है । ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान क्षेत्र के करीब 26 ग्राम जो नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना से छूटे है, उन ग्रामो के ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भेंट कर नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना में आष्टा विधानसभा क्षेत्र के छुटे 26 ग्रामो को जोड़ने की मांग को लेकर विस्तार से जानकारी दी एवं विधायक इंजीनियर ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की, कि उक्त योजना में इन ग्रामो को जोड़ा जाये । विधायक ने मुख्यमंत्री जी को सौपे मांग पत्र में जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरदड, टीपुपुरा, झॉझनपुरा, सामरीबोंदा, निमवरा, कातला, धुँराडाकला, धुँराडाखुर्द, धीगांखेडी, गुराडियावर्मा, बरछापुरा, ग्वाला, बीलपान, खटसुरा, कबीरखेडी, निजामडी, गुराडियामन्डा, मोहम्मदपुर, अंबिका नगर जावर, मालीपुरा, खजूरिया, अरोलिया, बाजखेडी , कालापीपल, हरनावदा, मुरावर नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना से छूटे है, इन ग्रामो का इस योजना से जुड़ना अति आवश्यक है, ताकि इन 26 ग्रामो के अन्नदाता किसान भाईयों को सिंचाई की एक बड़ी सुविधा मिल सके और ये पूरा क्षेत्र भी हराभरा हो सके । मुख्यमंत्री ने पूरी मांग को विस्तार से सुन कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है ।

वाहन चालकों को पढ़ाए नियमों के पाठ, नहीं मानने पर की चालानी कार्रवाई

आष्टा, देशबन्धु। सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में आपकी सुरक्षा में खड़ी पुलिस कभी प्यार से समझाती तो कभी चालानी कार्यवाही करके नियमों का एहसास कराती। चिलचिलाती धूप उमस व गर्मी के बीच यातायात चौकी प्रभारी शशिकांत शर्मा एवं उनके सहयोगी पुलिस के जवान नगर की यातायात व्यवस्था बनाने के साथ साथ अन्य रोडों पर जाम की स्थिति न बने एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों का हवाला देकर चैकिंग अभियान भी चलाया जाता है। 15 घंटे से भी अधिक ड्यूटी पर रहने वाले जवान आम लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। अब समय यह भी है कि आम लोगों को भी अपनी ओर दूसरों की सुरक्षा का ध्यान मे रखते हुए नियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाना होगा। साथ में वाहन के जरूरी दस्तावेज के साथ साथ वाहन चलाते समय कभी भी नशे का सेवन न करें।

मत्स्याखेट और खरीदी बिक्री पर 15 अगस्त तक मत्स्याखेट रहेगा प्रतिबंध

रायसेन, देशबन्धु। प्रदेश में मप्र नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3-(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बन्द ऋतु (मत्स्य प्रजनन काल) घोषित किया गया है। कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा के आदेशानुसार इस अवधि में जिले में मत्स्याखेट मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं मत्स्य परिवहन करना निषेध किया गया है। मप्र शासन मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिसको निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उन्हें छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री सिलवानी और गैरतगंज में जनकल्याण शिविर में हुए शामिल

खेत बचाओ अभियान, एकीकृत और आधुनिक कृषि से बदलेगी किसानों की तस्वीर : चौहान

- **लाड़ली बहना से आगे अब हर बहन बनेगी लखपति दीदी, आत्मनिर्भरता का नया अभियान**

रायसेन, देशबन्धु। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के सिलवानी और गैरतगंज के दौरे पर थे। केन्द्रीय मंत्री ने सिलवानी और गैरतगंज में आयोजित जन-कल्याण शिविर में शिरकत कर हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। उन्होंने सिलवानी में सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और अस्पताल परिसर में पौधरोपण भी किया।

श्री चौहान ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अलग-अलग विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर पारदर्शी तरीके से पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मंच से सार्वजनिक रूप से हितलाभ वितरण करने से पारदर्शिता बनी रहती है और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए और पात्र हितग्राहियों को बिना विलंब लाभ दिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्षेत्र के अनेक गांवों की सड़कों को स्वीकृति दी गई है और संबंधित ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। सिलवानी अस्पताल में नए भवन के साथ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने कहा कि जनकल्याण शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का विभागवार परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार शीघ्र लाभ उपलब्ध कराया जाएगा और जिला प्रशासन इस प्रक्रिया की सतत निगरानी करेगा।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को अब तक 13 लाख से भी अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि चल रहे फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पूरी संवेदनशीलता बरती जाए और किसी वास्तविक पात्र गरीब का नाम गलती से भी सूची से बाहर न हो। उन्होंने कहा कि जिनके पास कच्चा मकान है, उन्हें हर हाल में पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है और भविष्य में इसकी राशि बढ़ाने का संकल्प भी कायम है। उन्होंने कहा कि अब सरकार का अगला लक्ष्य प्रदेश की हर महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ष्लखपति दीदीष् बनाना है। श्री चौहान ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, बैंक ऋण और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक करने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और शहरों में अधिक से अधिक महिलाओं को समूहों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

उन्होंने कहा कि बदलते समय में खेती को वैज्ञानिक और लाभकारी बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रायसेन जिले के लिए विशेष कृषि रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें खेत बचाओ अभियान के तहत मिट्टी की जांच, संतुलित खाद का उपयोग और फसल विविधीकरण पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि छोटे जोत वाले किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी और सब्जी उत्पादन को जोड़कर आय बढ़ाई जाएगी। किसानों को गांव स्तर पर वैज्ञानिक, मिट्टी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त फसलों की जानकारी भी देंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना के तहत पंचायतों को हजारों करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अब योजनाएं दिल्ली या भोपाल में नहीं बनेंगी। ग्राम सभा स्वयं तय करेगी कि गांव में तालाब बनना है, खेत सड़क बननी है। पंचायत भवन बनना है या अन्य विकास कार्य किए जाने हैं।

रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहावना

किसान कर बौवनी की तैयारी

आष्टा, देशबन्धु। 15 जून से बारिश का मौसम प्रारंभ होता है जिसकी शुरूआत सोमवार से शुरू हो चुकी है, सुबह से ही हवा घने बादल से क्षेत्र घुला रहा जिसके चलते जहां गर्मी से राहत मिली वहीं साथ में दोपहर बाद रिमझिम बारिश से शुरू हुआ यह सिलसिला रूकरूक कर शाम तक चलता रहा। बारिश ओर हवा चलने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं क्षेत्र में समय पर बारिश शुरू होने से किसानों के चहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। किसान सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि अनाज का बीच लेकर पूरी तरह तैयार बैठा है, वहीं साथ में खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है। किसान खाद बीज के साथ साथ खेतों में बक्खर चला कर तैयार कर रहा है। बारिश की शुरूआत भले ही रिमझिम बारिश से हुई पर समय पर हुई। अगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई तो किसान बौनी का कार्य प्रारंभ कर देगा।

आंधी तूफान के चलते पेड़ हुए धराशायी, फलदार वृक्षों को सबसे अधिक नुकसान : कुछ दिन पहले भी आंधी तूफान से कई पेड़ धराशायी हो गए थे, फिर क्षेत्र में तेज हवा चली और पेड़ के डगाले टूट कर गिरने लगी साथ में सबसे अधिक नुकसान देसी आम के पेड़ को हुआ, तेज हवा के चलते जहां केरियां पुरी तरह से झड़ चुकी साथ में आम के पेड़ भी जगह जगह धराशायी हो गए। बताया जाता है कि मानसून की शुरूआत में आम खजूर जामन करोंदे आदि फल पकते है एवं मिठास भी आती है। बारिश की शुरूआत हो चुकी है, हुए मौसम परिवर्तन से एसा लगता है कि देर रात तक अधिक बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, बौवनी की तैयारी में किसान

आष्टा, देशबन्धु। 15 जून से बारिश का मौसम प्रारंभ होता है जिसकी शुरूआत सोमवार से शुरू हो चुकी है, सुबह से ही हवा घने बादल से क्षेत्र घुला रहा जिसके चलते जहां गर्मी से राहत मिली वहीं साथ में दोपहर बाद रिमझिम बारिश से शुरू हुआ यह सिलसिला रूकरूक कर शाम तक चलता रहा। बारिश ओर हवा चलने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं क्षेत्र में समय पर बारिश शुरू होने से किसानों के चहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। किसान सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि अनाज का बीच लेकर पूरी तरह तैयार बैठा है, वहीं साथ में खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है। किसान खाद बीज के साथ साथ खेतों में बक्खर चला कर तैयार कर रहा है। बारिश की शुरूआत भले ही रिमझिम बारिश से हुई पर समय पर हुई। अगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई तो किसान बौनी का कार्य प्रारंभ कर देगा।

मोसम में घुली ठंडक, मानसून की तरह बरसा प्री मानसून

सुबह से बना माहौल दोपहर में हुई झमाझम बारिश

रायसेन, देशबन्धु। मानसून से पहले प्री-मानसून की बारिश ने सोमवार को जिलेभर को तरबतर किया। सुबह से आसमान में बार-बारछा रहे बादल दोपहर बाद साढ़े तीन बजे जमकर बरसे। जिससे मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 38 तथा न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा।

लगभग एक घंटे तक शहर सहित जिले में कई जगह बारिश हुई। बारिश से पहले आसमान में घने बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश ने वातावरण को ठंडा कर दिया।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं। अगले कुछ दिनों तक जिले में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 18 से 20 जून के बीच मानसून के मध्यप्रदेश में और आगे बढने की संभावना है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो रायसेन जिले में भी इसी अवधि के दौरान मानसून की दस्तक हो सकती है।

कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जलाया पुतला

मीनाक्षी का नामांकन रद्द होना संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार : पटेल

रायसेन, देशबन्धु। राज्य सभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना केवल एक उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रहार है। यह बात जिला कांग्रेस प्रभारी शैलेंद्र पटेल ने कही।

सोमवार को पटेल ने जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए पटेल ने कहा कि जिस प्रकार की आपत्तियों और व्याख्याओं के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्तर किया गया, उसने पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े किए हैं। पटेल ने कहा, जिस निजी परिवाद के आधार पर नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, उसमें उन्हे अभियुक्त नहीं, बल्कि प्रतिवादी के रूप में दर्शाया गया है। प्रतिवादी और अभियुक्त की कानूनी स्थिति अलग-अलग होती है। उन्होंने कहा कि नामांकन में जो जानकारी मांगी ही नहीं गई, उसे क्यों दिया जाए।

युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन : शाम को युवक कांग्रेस ने सागर तिराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर उसका दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शैलेंद्र पटेल, सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, ब्लाक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह सोलंकी, जावेद अहमद, राजू माहेश्वरी, हसीब हिंदुस्तानी आदि मौजूद थे।

बीटीआई में आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सीहोर, देशबन्धु। वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय में मध्यप्रदेश एसडीईआरएफ और होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस के सहयोग से एक दिवसीय अग्निशमन और आपदा प्रबंधन का प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वीआईटी के आडिटोरियम में प्रशिक्षण के पहले चरण में भोपाल मुख्यालय से एसडीईआरएफ कमांड सेंटर के पी. सी. मनोज कुमार बातव, पी. सी. शरद यादव, पी.सी. महेंद्र वर्मा, एएसआई ए. एस. चंदेरिया और भोपाल नगर निगम के फायर आफिसर शक्ति कुमार तिवारी ने आपदा के अलग अलग बिदुओं पर स्टाफ को गहन प्रशिक्षण दिया 7 इस दौरान उपस्थित लोगो की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

इसके बाद एसडीईआरएफ कमांड सेंटर से आये अधिकारियो ने केम्पस में पांच मंजिला से आपदा प्रभावित लोगो का रेस्क्यू प्रभावी माकड्रिल किया 7 इस दौरान रेस्क्यू किये गए विक्टिम को सीपीआर दिया गया और एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर किया गया । इस अवसर पर आयोजित समारोह में भोपाल मुख्यालय से आये एसडीईआरएफ कमांड सेंटर के अधिकारियो को शाल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया । इस मौके पर होमगार्ड के संभागीय कमांडेंट कमलेन्द्र परिहार, एसडीईआरएफ के स्टेट कमांड सेंटर प्रभारी डिस्ट्रिक्ट कमान्डेंट कमलनाथ धुर्वे को वीआईटी भोपाल के रजिस्ट्रार के. के. नायर, आपरेशन डायरेक्टर डॉ. एस. प्रभाकरण, हॉस्टल काउन्सिल मेम्बर सेक्रेट्री डॉ जस्टिन सैमुअल और डिप्टी डायरेक्टर सुरक्षा राहुल मुखी ने सम्मानित किया। साथही भोपाल मुख्यालय से आये एसडीईआरएफ के स्टेट कमांड सेंटर के 35 सदस्यीय दल को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मनित किया गया।

पौधरोपण कर मनाया जन्मदिन, मां की याद में लगाए पौधे

सीहोर, देशबन्धु। आज सीवन उद्धार का 83 वां दिवस के रूप में सीवन पुत्र जितेंद्र आर्य के जन्मदिन के अवसर पर उनकी दिवंगत मां की याद में पौधे जो की तिलक पर एक्सीलेंस स्कूल के सामने रोपें गए,ज्ञात हो कि सीवन पुत्र सीवन उद्धार के तहत ही पौधारोपण का कार्यक्रम चल रही है विगत कई दिनों से वह ड्रॉप का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आज इसी कड़ी में फिर से पौधे रुपए गए।

सीवन पुत्र प्रदीप चावड़ा ने बताया कि जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, पुण्यतिथि आदि विशेष अवसर पर लोगों से पौधे लगवाए जाते हैं ताकि यह खास अवसर किस सार्थकता सिद्ध हो।

इस अवसर पर ट्रस्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री संतोष सोनी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे उन्होंने सीवन पुत्र टीम की के कार्यों की हृदय से प्रशंसा की है एवं उनके कार्यों में सहभागी बने का भी उन्होंने वादा किया है।

इस अवसर पर सीवन पुत्र अशोक नामदेव, कनीराम मालवीय विभव राठौर, सुरेश भगत,जितेंद्र आर्य, संतोष सोनी, प्रदीप चावड़ा, मुकेश राय,जगदीश वर्मा,कैलाश चव्हाण भोला ठाकुर, चंद्रशेखर राजपूत आदि उपस्थित रहे।

महिलाओं की चैन उड़ाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार

पुलिस ने 3 दिन में सुलझाई वारदात, 50 लाख का माल बरामद

देवास, देशबन्धु। धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालु बनकर महिलाओं के गले से सोने की चैन चोरी करने वाले अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का देवास पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मात्र 3 दिनों में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 7 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 156 ग्राम वजन की 9 सोने की चैन, एक लग्जरी कार, 6 महंगे मोबाइल फोन सहित करीब 50 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है।

गिरोह में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। सभी आरोपी मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं तथा लंबे समय से दक्षिण दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरोह ने जून माह के पहले 15 दिनों में आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर और देवास में कुल 9 वारदातों को अंजाम दिया था।

पुलिस के मुताबिक 11 जून को राधागंज निवासी सरोज अग्रवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जून को मंडी व्यापारी एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात महिला ने उनके गले से करीब साढ़े 3 लाख रुपए कीमत की सोने की चैन और पेंडल चोरी कर लिया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी करीब 500 मीटर पैदल चले, फिर ऑटो से लगभग 2 किलोमीटर दूर हाईवे तक पहुंचे और वहां खड़ी अपनी लग्जरी कार में बैठकर फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पता चला कि गिरोह भोपाल में अगली वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। पुलिस टीम ने भोपाल पहुंचकर घेराबंदी की और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने देवास सहित आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी और जबलपुर में कुल 9 चैन चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया। सभी चोरी गई 9 सोने की चैन भी बरामद कर ली गई हैं।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह की महिला सदस्य भागवत कथा, प्रवचन, मेले, शोभायात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालु बनकर पहुंचती थीं। आरती, प्रसाद वितरण और भीड़भाड़ के दौरान महिलाओं के नजदीक जाकर बड़ी सफाई से उनके गले से सोने की चैन निकाल लेती थीं। वहीं पुरुष सदस्य निगरानी, परिवहन और चोरी के माल को ठिकाने लगाने का काम करते थे।

स्मार्ट मीटर से बढ़े बिलों को लेकर बढ़ी नाराजगी

उपभोक्ताओं ने तेज रीडिंग का जताया संदेह, विद्युत वितरण कंपनी ने जांच का दिया भरोसा

__सांची, देशबन्धु।__ नगर में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बड़े स्तर पर लगाए गए स्मार्ट मीटर अब चर्चा और शिकायतों का विषय बनते दिखाई दे रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार करते हुए जांच की सुविधा उपलब्ध होने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को आधुनिक सुविधा और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर में बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए थे। प्रारंभिक दौर में इन मीटरों को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया, लेकिन अब कुछ उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

उपभोक्ताओं का कहना है कि हाल के समय में बिजली बिलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि नगर में बढ़ती आबादी, घरेलू उपकरणों के बढ़ते उपयोग तथा कुल बिजली खपत में वृद्धि का असर भी बिलों पर दिखाई दे सकता है।

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी सामने आ रही है कि कुछ क्षेत्रों में अवैध बिजली उपयोग एवं अनधिकृत कनेक्शनों की समस्या बनी हुई है। वैध उपभोक्ताओं का मानना है कि यदि बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ सकता है।

इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी के सहायक प्रबंधक मनीष कुमार ने कहा कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर अनावश्यक संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता को बिल अधिक आने की आशंका है तो वह मंडल कार्यालय में संपर्क कर बिल, मीटर और बिजली खपत की जांच करवा सकता है। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार बिजली चोरी के मामलों की निगरानी कर रहा है तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बढ़ते बिजली बिलों के बीच अब उपभोक्ताओं की नजर जांच और पारदर्शिता पर टिकी है, ताकि स्मार्ट व्यवस्था पर बना विश्वास कायम रह सके।

सार समाचार

पत्रकार को पत्नी शोक

सिरोंज, देशबन्धु। पत्रकार रोहिताश्व शर्मा की धर्मपत्नी भावना शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा सोमवार को दोपहर 12 बजे निज निवास रावजी पथ से प्रारंभ होकर तहसील रोड मुक्तिधाम पहुंची। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्यां में मौजूद लोगों ने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।

भूमि मुआवजा प्रकरण में उच्च न्यायालय सख्त, तीन माह में निर्णय लेने के निर्देश

जबलपुर, देशबन्धु। हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़े मामले में सक्षम प्राधिकारी को समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता रायसेन निवासी मोहम्मद असलम की ओर से ग्राम नीमखेड़ा पटवारी हल्का क्रमांक 39, तहसील एवं जिला रायसेन स्थित खसरा नंबरों की अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में दायर रिट याचिका दायर की गई थी। जिसका निराकरण 5 फरवरी 2025 को करते हुए सक्षम प्राधिकारी को विधि अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, किंतु आदेश के बावजूद अब तक अनुपालन लंबित है। जिसके बाद न्यायालय ने मामले का निराकरण करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करें। प्राधिकारी पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले का विधि अनुसार शीघ्र निराकरण करें तथा समस्त कार्यवाही अधिकतम तीन माह के भीतर पूर्ण की जाए। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा जताई कि सक्षम प्राधिकारी प्रकरण की स्थिति से याचिकाकर्ता को समयबद्ध रूप से अवगत कराए।

पेट्रोल पंप पर किसानों का प्रदर्शन: केन-कुप्पे में डीजल न मिलने के आदेश का विरोध

बीना, देशबन्धु। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने सोमवार को सर्वोदय चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केन, ड्रम और कुप्पे में डीजल न दिये जाने के सरकारी आदेश के विरोध में किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य पेट्रोल पंप पर डीजल लेने पहुंचे थे। उन्होंने कुप्पे में डीजल देने का आग्रह किया, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने शासन के आदेश का हवाला देते हुये इनकार कर दिया। इसके बाद किसानों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन किसानों के पास एक से दो एकड़ जमीन है, उनके लिये हर बार ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप आना संभव नही है। केन-कुप्पे में डीजल ले जाना उनकी मजबूरी है। उन्होंने इस निर्णय को छोटे किसानों के लिये नुकसानदेह बताया। संयुक्त किसान मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष सीताराम ठाकुर ने कहा कि आज किसानों की किसानी खतरे में है। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्यूबवेल, जेसीबी और अन्य बड़े उपकरणों के लिये तो टंकियों में डीजल पहुंच जाता है, लेकिन किसानों को कुप्पे में डीजल देने पर रोक है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह सरकार उद्योगपतियों के लिये काम कर रही है, किसानों के लिये नही। जब घर-घर शराब बिक सकती है, तो सरकार को किसानों के लिये डीजल भी घर-घर पहुंचवाना चाहिये। उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं को समझने का आग्रह किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि छोटे किसानों को खेती के लिये केन कुप्पे में डीजल लेने की छूट दी जाये। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश में बदलाव नहीं किया गया, तो वे आगे आंदोलन करने को विवश होंगे।

शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा

दहेज मौत या हत्या? न्याय के लिए भटकता पिता

विदिशा, देशबन्धु। विदिशा में एक पिता अपनी बेटी की मौत को हत्या बताते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही।

ये तस्वीरें और दस्तावेज किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भर नहीं हैं, बल्कि एक पिता के दर्द और इंसाफ की लड़ाई की कहानी बयां कर रहे हैं। ग्राम भौरिया निवासी मीठालाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी सलोनी की शादी आशीष उर्फ नैतिक किरार से हुई थी। शादी

के कुछ समय बाद से ही सलोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।

पीड़ित पिता का आरोप है कि पति, सास, जेठ और जेठानी द्वारा मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन और 10 लाख रुपये नकद की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर सलोनी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। 13 मई 2026 को सलोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायका पक्ष इसे सुनियोजित हत्या करार दे रहा है।

परिजनों का कहना है कि घटना के करीब 20 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष राजनीतिक प्रभाव वाला है और इसी वजह से कार्रवाई में देरी हो रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है।

'मेरी बेटी को दहेज के लिए लगातार परेशान किया गया। उसकी हत्या हुई है। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर हमें न्याय दिलाया जाए।'

सोमवार को एक बार फिर पीड़ित पिता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की

उपमहाप्रबंधक राजगढ़ पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप

प्रबंध संचालक को ज्ञापन सौंपकर लगाई न्याय की गुहार

विदिशा, देशबन्धु। रुपाली चौहान पत्नि मेवालाल चौहान ने प्रबंध संचालक म.प्र.म.क्षे. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल को एक ज्ञापन देकर उपमहाप्रबंधक राजगढ़ राजीव रंजन द्वारा आर्थिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की है।

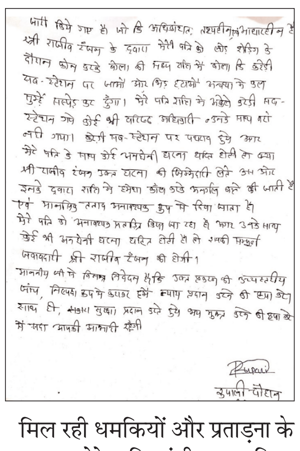

ज्ञापन के माध्यम से रूपाली चौहान ने बताया कि मेरे पति मेवालाल चौहान वर्तमान में राजगढ़ वितरण केन्द्र में पदस्थ है। राजीव रंजन द्वारा मेरे पति को सन् 2019 से निरंतर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। राजीव रंजन द्वारा अनेकों अवसरों पर मेरे पति को खुलेआम कैरियर तबाह करते हुए वेतनवृद्धि जीवनभर नहीं देंगे ऐसी धमकी 2015 से देते आ रहे हैं। आष्टा में भी झूठे आरोप लगाकर निलंबित कराया गया था। जबकि जांच के बाद मेरे पति दोषमुक्त पाए गये थे। मेरे पति के लिये उनके व्यवहार से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने के कारण के दुर्भावना व्यक्तिगत रखते है एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी करते है और रोजाना सस्पेंड करने और भारी भाकम रिकवरी निकालने की धमकी भी देते हैं। उनके द्वारा बोला जाता है कि जीवन भर तक रिकवरी भरते रहोगा। लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना के कारण मेरे पति गंभीर, मानसिक तनाव में जीवन व्यतीत कर रह हैं। विगत दिनों में राजीवन रंजन द्वारा मेरे पति को लगभग 18-20 कारण बताओ नोटिस और स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए गए हैं जो कि अधिकांशत= तथ्यहीन और आधारहीन हैं। मेरे पति के साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जवाबदारी राजीव रंजन की होगी।

रूपाली चौहान ने ज्ञापन के माध्यम से उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच, निष्पक्ष रूप से कराकर न्याय दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है ताकि वह भय मुक्त होकर जीवन जी सके।

सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण का तीसरा सत्र शुरू

विदिशा, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय बैच का शुभारंभ आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा डॉ. प्रशांत चौबे की उपस्थिति में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15 जून 2026 से 20 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के आदेशानुसार जिले के विभिन्न थाना एवं पुलिस इकाइयों से कुल 40 अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस बैच में सम्मिलित हुए हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य वर्ष 2028 में महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ महापर्व के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं, सुरक्षा चुनौतियों एवं भीड़ प्रबंधन संबंधी दायित्वों के लिए दक्ष एवं सक्षम बनाना है।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंहस्थ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे विशाल आयोजन में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को गंभीरता, अनुशासन एवं समर्पण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर उसे व्यवहारिक रूप से लागू करने हेतु प्रेरित किया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सिंहस्थ परिचय, सिंहस्थ-2016 का पुनरावलोकन, विभिन्न पुलिसिंग जिम्मेदारियां, सिंहस्थ हेतु जोन विभाजन, अस्थायी थानों की स्थापना, बल वितरण, भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन, श्रद्धालुओं की आवाजाही का प्रबंधन, अभिसूचना संकलन, आतंकवादी एवं नक्सली संगठनों से संबंधित सुरक्षा पहलू, वीआईपी आगमन के दौरान व्यवस्थाएं, विभिन्न अखाड़ों एवं उनके महंतों का परिचय, अखाड़ा पेशवाई जुलूस प्रबंधन, यातायात योजना, आपातकालीन योजना एवं ग्रीन कॉरिडोर, आपदा प्रबंधन, पुलिस बल की आवास व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, रेडियो संचार प्रणाली, सिंहस्थ सुरक्षा एवं संभावित खतरों से बचाव, विस्फोटक पदार्थों की पहचान एवं सुरक्षा उपाय, सोशल एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से फैलने वाली अफवाहों का नियंत्रण, सॉफ्ट स्किल, उच्च आचरण एवं व्यवहार, चिकित्सीय व्यवस्थाएं तथा क्विक रिस्पांस अरेंजमेंट सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

जिला पुलिस द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सिंहस्थ-2028 के दौरान उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावी भीड़ प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता एवं बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस बल को आयोजन के प्रत्येक पहलू से अवगत कराते हुए उन्हें किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु तैयार किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन से बदली ग्राम चवरिया की तस्वीर

भोपाल। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड का छोटा सा आदिवासी ग्राम चवरिया आज ग्रामीण परिवर्तन की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरा है। कभी जहां पेयजल की उपलब्धता गांववासियों के लिए दैनिक संघर्ष का विषय थी, वहीं आज जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से गांव के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

गांव की महिलाओं के लिए पानी जुटाना जीवन का सबसे कठिन कार्य था। प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस प्रक्रिया में न केवल उनका समय और श्रम व्यय होता था, बल्कि परिवार और बच्चों की देखभाल सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित होते थे। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में यह चुनौती और अधिक बढ़ जाती थी।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम चवरिया में पाइप आधारित जल प्रदाय व्यवस्था विकसित किए जाने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब गांव के सभी 79 परिवारों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है और महिलाओं को पानी की चिंता से मुक्ति मिली है।

गांव की महिलाओं का कहना है कि अब उनके पास बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने, घरेलू कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने तथा कृषि गतिविधियों में सहयोग देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। पहले जो समय पानी लाने में व्यतीत होता था, वह अब परिवार और आजीविका से जुड़े कार्यों में लग रहा है। इससे उनके जीवन में सुविधा के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

जल जीवन मिशन ने केवल पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य नहीं किया, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। गांव में जल प्रदाय व्यवस्था के संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

सिंगापुर में हुए ट्रेड बिजनेस डेवेलपमेंट प्रशिक्षण में

एमएसएमई की टेंभरे ने किया भारत का प्रतिनिधित्व

भोपाल, देशबन्धु। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सहायक संचालक श्रीमती ओजस्वी टेंभरे ने सिंगापुर सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सिंगापुर पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण में 'ट्रेड बिजनेस डेवेलपमेंट' में भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश एवं देश को गौरान्वित किया। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत से केवल एक प्रतिभागी का चयन किया गया था जिसमें श्रीमती ओजस्वी टेंभरे को देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ।

8 जून से 12 जून 2026 तक सिंगापुर के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्व के लगभग 25 देशों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को व्यापार एवं व्यवसाय विकास, निवेश संवर्धन, उद्यमिता विकास, नवाचार, आर्थिक प्रगति, वैश्विक सहयोग तथा संस्थागत क्षमता निर्माण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराना था।

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जैकिट का प्रदर्शन: श्रीमती टेंभरे द्वारा मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत प्रसिद्ध शिवपुरी जैकेट को सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के अधिकारीगण को स्मृति-चिह्न/उपहार स्वरूप भेंट किया गया। उन्होंने शिवपुरी जैकेट की विशेषताओं, स्थानीय कारीगरों के हुनर तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थानीय उत्पादों के संवर्धन संबंधी पहलों की जानकारी भी साझा की। इस पहल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा, स्थानीय उत्पादों तथा वोकल फॉर लोकल की भावना का प्रभावी प्रदर्शन किया गया।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को सिंगापुर के आर्थिक विकास मॉडल, व्यापार एवं निवेश संवर्धन तंत्र, उद्यमिता एवं स्टार्टअप पारितंत्र, कौशल विकास कार्यक्रमों, नवाचार आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली की सफल कार्यप्रणालियों का अध्ययन कराया गया। विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, संवादात्मक सत्रों एवं अध्ययन भ्रमणों के माध्यम से प्रतिभागियों को वैश्विक स्तर की नीतियों, व्यवहारिक अनुभवों एवं सफल मॉडलों की जानकारी प्रदान की।कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को सिंगापुर के उद्योग, व्यापार एवं नवाचार प्रणालियों का प्रत्यक्ष अध्ययन कराने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों एवं नवाचार केंद्रों का भ्रमण भी कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती ओजस्वी टेंभरे ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टार्टअप, नवाचार एवं व्यापार संवर्धन के क्षेत्र में अपनाई जा रही वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का अध्ययन किया।

दागी अफसर खुद अपनी जांच की निगरानी कैसे कर सकता है?

उच्च न्यायालय ने निरस्त किया मुख्य अभियंता का प्रभार

जबलपुर, देशबन्धु। मप्र हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में नियमों को ताक पर रखकर दागी अधिकारियों को बड़ा प्रभार सौंपने की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है । न्यायालय ने भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता (चीफइंजीनियर) के पद से जुड़े एक विवादित प्रशासनिक आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है । जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के जिस दफ्तर को दागी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी दफ्तर की कमान उसे सौंप दी गई। यह प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है।

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार किसी ऐसे योग्य अधिकारी को सौंपें जिसका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह निष्कलंक हो और जो पदोन्नति की पात्रता श्रेणी में आता हो। राज्य के मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को आवश्यक अनुपालन और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं।

यह है मामला-मामला पीडब्ल्यूडी के प्रभारी मुख्य अभियंता पीसी वर्मा से जुड़ा है । उन्हें जुलाई 2025 में मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी ब्रिज जोन भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था । इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को विभाग ने उन्हें निविदा मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस नोटिस के जारी होने के महज तीन घंटे के भीतर ही विभाग ने एक नया आदेश जारी कर पीसी वर्मा से अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया । यही नहीं, यह प्रभार भोपाल जोन के मुख्य अभियंता का कार्यभार संभाल रहे एक अन्य अधिकारी को सौंप दिया गया, जिनके खिलाफपहले से ही गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और पुल ढहने के मामलों में जांच लंबित है। विभाग के इसी आदेश को पीसी वर्मा ने हाईकोर्ट में संजय कुमार मस्के के प्रभार को चुनौती दी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई दौरान राज्य सरकार की इस कार्रवाई को पूर्वाग्रह से ग्रसित और दुर्भावनापूर्ण माना। न्यायालय ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि जिस अधिकारी को नया प्रभार सौंपा गया, उसके खिलाफसिवनी में वैनगंगा नदी पर बने सबमर्सिबल पुल के ढहने और ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल प्रोजेक्ट में करीब 2.41 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय गबन के गंभीर आरोप हैं।

लगभग सवा आठ लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

मई माह में 'टाइम ऑफ डे' टैरिफ के तहत मिला 8 करोड़ 41 लाख 52 हजार की छूट का लाभ

भोपाल, देशबन्धु। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग?वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मई का महीना राहत लेकर आया है। कंपनी द्वारा स?मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को %टाइम ऑफ डे% (ज्ञश्ष्ठ) टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर ऑवर (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई है। इस %टाइम ऑफ डे% (ज्ञश्ष्ठ) टैरिफ व्यवस्था के तहत कंपनी कार्यक्षेत्र में कुल 8 लाख 17 हजार 302 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मई माह के बिजली बिल में 8 करोड़ 41 लाख 52 हजार रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आधुनिक तकनीक को अपनाएं और अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगवाने हेतु आगे आएं। स्मार्ट मीटर न केवल ऊर्जा संरक्षण में सहायक हैं, बल्कि यह उपभोक्ताओं को अपनी खपत के प्रति जागरूक कर आर्थिक लाभ भी दिला रहा है। स्मार्ट मीटर हर 15 मिनट में बिजली खपत का सटीक डेटा रिकॉर्ड करते हैं और खपत का डेटा स्वचालित रूप से बिलिंग सर्वर को प्राप्त होता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग के समय को प्रबंधित कर %टाइम ऑफ डे% टैरिफ जैसी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने बिलों में बचत कर सकते हैं।स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) अवधि के दौरान उपयोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक?ताओं को 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। स्मार्ट मीटर के संबंध में उपभोक?ता किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के निराकरण हेतु कॉल सेन?टर 1912 अथवा नोडल अधिकारी श्री कैलाश कुमार चौधरी, प्रबंधक(स्मार्ट मीटरिंग सेल) से ईमेल आईडी Smartmeteringcellbhopal@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

सिरोजा में हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा, 2 शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार

सागर, देशबन्धु। थाना सिविल लाइन पुलिस ने सिरोजा क्षेत्र में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुये दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 4 लाख रुपये मूल्य के सोने चांदी के जेवरात तथा वारदात में प्रयुक्त होंडा एसपी.125 मोटरसाइकिल बरामद की है। 13 अप्रैल 2026 को फरियादी विष्णु सिंह पिता अनंत सिंह ठाकुर 58 वर्ष निवासी चार पुलिया के पास सिरोजा ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 व 13 अप्रैल की दरम्यानी रात अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर गोदरेज अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गये। रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य एकत्रित किये। जांच के आधार पर जितेन्द्र उर्फ मजले पिता रामकिशन विश्वकर्मा निवासी झील मोहल्ला ग्राम भटेरा जिला नरसिंहपुर एवं सुरेन्द्र उर्फ विक्की पिता गोकुल प्रसाद ठाकुर निवासी ग्राम घनसोर थाना केवलारी जिला सिवनी की संलिप्तता सामने आई। दोनों आरोपी अन्य थाना क्षेत्रों के मामलों में भी वांछित पाये गये। पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।

लगातार तलाश एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खोजबीन की गई

शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अपहृता ग्वालियर से सकुशल दस्तयाब

विदिशा, देशबन्धु। दिनांक 19.05.2026 को थाना पठारी क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण की सूचना प्राप्त होने पर थाना पठारी में अपराध क्रमांक 73/26 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी अरविंद पिता प्राण सिंह परिहार नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था तथा उसके साथ गलत कार्य किया। प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 87, 65(1), 64(2)(एम) बीएनएस एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट

का इजाफा किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे तथा एसडीओपी कुरवाई सुश्री रोशनी सिंह के मार्गदर्शन में थाना पठारी पुलिस द्वारा लगातार तलाश एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खोजबीन की गई। पुलिस टीम ने डबरा, जिला ग्वालियर से नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

पुलिस द्वारा आरोपी अरविंद पिता प्राण सिंह परिहार, निवासी ग्राम कैथी, थाना चिनोर, जिला ग्वालियर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

सराहनीय भूमिका: उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ऋतुराज सिंह, प्रधान आरक्षक उत्तम वर्मा एवं आरक्षक वीरेंद्र कुमार की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

विदिशा पुलिस महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

अर्थ जगत

चालू खाते में अप्रैल में 4.7 अरब डॉलर का आधिक्य

मुंबई, 15 जून (एजेंसियां)। वस्तु व्यापार घाटा बढ़ने के बावजूद इस साल अप्रैल में देश ने चालू खाते में 4.7 अरब डॉलर का आधिक्य दर्ज किया। इसका मतलब यह है कि चालू खाते में आमद ज्यादा रही। रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार, सेवाओं का निर्यात ज्यादा तेजी से बढ़ने और विदेश से भेजे गये मनीऑर्डर बढ़ने के कारण चालू घाटे में आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछले साल अप्रैल में चालू खाते में 4.8 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया गया था।

सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर

ट्रेंट	5.35 प्रतिशत
इंडिगो	3.59 प्रतिशत
बजाज फिनसर्व	3.58 प्रतिशत
अल्ट्राटेक सीमेंट	3.29 प्रतिशत
इटरनल	3.26 प्रतिशत

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

एनटीपीसी	1.64 प्रतिशत
आईसीआईसीआई बैंक	0.94 प्रतिशत
हिंन्दुस्तान यूनिलीवर	0.52 प्रतिशत
अडानी पोर्ट्स	0.49 प्रतिशत
सनफार्मा	0.40 प्रतिशत

सर्राफा

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	1,50,169
बिटुर	88,730
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	2,51,011
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	95.92	92.88
पौंड स्टर्लिंग	129.3	124.69
यूरो	111.87	1077.71
चीन युआन	14.91	13.19

अनाज

देसी गेहूँ एमपी	2400-3000
गेहूं दडा	2862.70
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चोकर	2000-2100

मोटा आनाज

बाजरा	1300-1305
मक्का	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जौ	1430-1440
काबुली चना	3500-4000

शुगर

चीनी एस	4293.58
चीनी एम	4500-4600
मिल डिलीवरी	3620-3720
गुड़	4986.64

दाल-दलहन

चना	5700-5800
दाल चना	7688.34
मसूर काली	8130.44
उड़द दाल	10910.92
मूंग दाल	10144.49
अरहर दाल	11185.49

विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार उठाएगी और कदम : सीतारमण

■ **विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बनाए रखना जरूरी**

हमें एहसास है कि देश में और अधिक विदेशी पूंजी आनी चाहिए : निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

नई दिल्ली, 15 जून (एजेंसियां)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार देश में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आगे भी कई कदम उठाएगी और बॉन्ड मार्केट के लिए हाल में घोषित उपाय इस दिशा में सिर्फ शुरुआत हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हीरो माइंडमाइन समिट 2026 को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि हम मानते हैं कि देश में और अधिक विदेशी पूंजी आने की जरूरत है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को विदेश से धन जुटाने की अनुमति देना इस कहानी का अंत नहीं है। हम आगे भी और कदम उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को समझती है और आरबीआई के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि बाजारों को आवश्यक निवेश मिलता रहे। वित्त मंत्री ने कहा, 'हम मानते हैं कि बॉन्ड मार्केट आने वाली विदेशी पूंजी को समाहित करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। फिलहाल यह सुविधा केवल सरकारी प्रतिभूतियों के लिए दी गई है, लेकिन यह अंतिम कदम नहीं है। हमें एहसास है कि देश में और अधिक विदेशी पूंजी आनी चाहिए। सीतारमण ने कहा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार है और खपत लगातार बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया भर के अन्य देशों और कारोबारों की तरह भारत भी कई ऐसी अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं।

घरेलू मांग से मिल रहा अर्थव्यवस्था को समर्थन : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि इस समय वैश्विक स्तर पर व्यापार और आपूर्ति को लेकर कई प्रकार की अनिश्चितताएं भारतीय अर्थव्यस्था के लिए चुनौती पेश कर रही हैं, हालांकि घरेलू मांग से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल रहा है। श्रीमती सीतारमण ने यहां 'माइंडमाइन सम्मेलन 2026' के एक संवाद सत्र के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वर्तमान में वैश्विक व्यापार में काफी अनिश्चितताएं हैं। हमारा निर्यात मजबूत है लेकिन अचानक आयात शुल्क बढ़ा दिया जाता है। हम जिन तीन वस्तुओं का सबसे अधिक आयात करते हैं उनकी कीमत और आपूर्ति दोनों में काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसके लिए विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सबके बीच भारत के लिए राहत की बात हमारा घरेलू बाजार है, जो काफी बड़ा है। घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। हालांकि विनिर्माताओं के समक्ष आयातित कच्चे माल की ऊंची कीमत की चुनौती भी है। घरेलू स्तर पर मानसून की चुनौती को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार अल-नीनो प्रभाव के कारण कम बारिश होने का अनुमान है। देश के पास अनाज का काफी बफर भंडार है, इसलिए खाद्यान्न की कमी जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन किसानों की आमदनी पर कम मानसून का असर जरूर होगा।

भारत का वस्तु निर्यात मई में बढ़कर 45.2 अरब डॉलर रहा

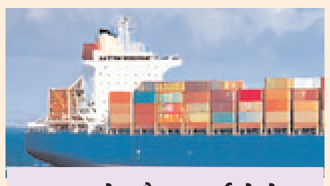

■ **भारत ने अप्रैल व मई दोनों महीनों में निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की**

नई दिल्ली, 15 जून (एजेंसियां)। भारत का वस्तु निर्यात मई में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 45.2 अरब डॉलर हो गया है। अप्रैल में यह 43.56 अरब डॉलर था। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए डेटा में दी गई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मई की वस्तु निर्यात वृद्धि को अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि दर में से एक बताया। अप्रैल 2026 में भी वस्तु निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, और यह अप्रैल 2025 में 38.28 अरब डॉलर था।

वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-मई महीने में देश का कुल निर्यात 88.91 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16.09 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

अग्रवाल ने कहा कि भारत ने अप्रैल और मई दोनों महीनों में निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि इसी दौरान आयात में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने मीडिया से कहा, 'अगर हम इसी रफ्तार को बनाए रखते हैं, तो वित्त वर्ष 27 व्यापार के लिहाज से एक अच्छा साल होगा।

मई में आयात 20.62 प्रतिशत बढ़कर 73.41 अरब डॉलर हो गया। इसके चलते व्यापार घाटा 28.21 अरब डॉलर रहा है। वहीं, मई 2025 में व्यापार घाटा 22.56 अरब डॉलर था, जो कि सालाना आधार पर 25.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। बीते महीने व्यापार घाटे में बढ़ोतरी की वजह पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाना है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट को होने वाले निर्यात, जिन पर पहले असर पड़ा था, उनमें मई में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया को होने वाला निर्यात लगभग मई 2025 के स्तर पर पहुंच गया है, और इसमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और यमन को भेजे गए सामान की वजह से बढ़ोतरी हुई है।

कीमती धातुओं में भारी उछाल, सोना-चांदी 3 प्रतिशत तक चढ़े

मुंबई, 15 जून (एजेंसियां)। अमेरिका और ईरान द्वारा शांति समझौते की पुष्टि के बाद, भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं में कमी आने से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार के साथ ही कीमती धातुओं में भी भारी उछाल देखने को मिली।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर अगस्त वायदा सोना अपने पिछले बंद 1,50,528 रुपए से 3,301 रुपए की भारी उछाल के साथ 1,53,829 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो खबर लिखे जाने तक दिन का उच्चतम स्तर रहा। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा अपने पिछले बंद 2,46,186 रुपए से 5,377 रुपए की जबरदस्त तेजी के साथ 2,51,563 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला और शुरुआती कारोबार में ही 3 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 2,53,345 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, खबर लिखे जाने तक (दोपहर 12.09 बजे के करीब) एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.48 प्रतिशत यानी 2,222 रुपए की उछाल के साथ 1,52,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

अंबाला मंडल में 'कवच' लगाने के लिए रेलवे ने दी परियोजना को मंजूरी

नई दिल्ली, 15 जून (एजेंसियां)। रेलवे सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने के लिए रेलवे ने उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के बचे हुए ब्रॉड गेज सेक्शन पर 'कवच' लगाने के लिए 201 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। रेलवे ने सोमवार को बताया कि इस परियोजना में 811 किलोमीटर मार्ग पर कवच लगाया जाएगा। यह मंजूरी भारतीय रेलवे के बचे हुए रूटों पर एलटीई-बेस्ड कम्युनिकेशन बैकबोन के साथ 'कवच' लगाने के छत्र कार्यक्रम के तहत दी गई है।

रेलवे के अनुार इसके तहत अंबाला मंडल के अंबाला कैंटोनमेंट-लुधियाना, कालका-चंडीगढ़-न्यू मोरिंडा-साहनेवाल, सरहिंद-दौलतपुर चौक, राजपुरा-बठिंडा-श्री गंगानगर और लुधियाना-धुरी-जाखल खंड शामिल होंगे। रेलवे ने बताया कि ये रूट हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ने वाले अहम रेल गलियारे हैं। इन पर यात्रियों और माल की भारी आवाजाही होती है और ये इस इलाके में लोगों और सामान के आने-जाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

गौरतलब है कि 'कवच' एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है जिसे परिचालन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

अहमदाबाद मंडल के लिए 140 करोड़ की 'कवच' परियोजना मंजूर

रेलवे ने रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में 'कवच 4.0' लगाने को मंजूरी प्रदान की है। रेलवे ने सोमवार को बताया कि 48 ब्लॉक सेक्शन और 598 किलोमीटर पर मार्ग पर 'कवच 4.0' लगाने के लिए 140 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी भारतीय रेलवे के बाकी रूटों पर दीर्घकालिक विकास (एलटीई)-बेस्ड कम्युनिकेशन बैकबोन के साथ 'कवच' लगाने के बड़े प्रोग्राम के तहत दी गई है।

लिवाली की बदौलत तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बाजार

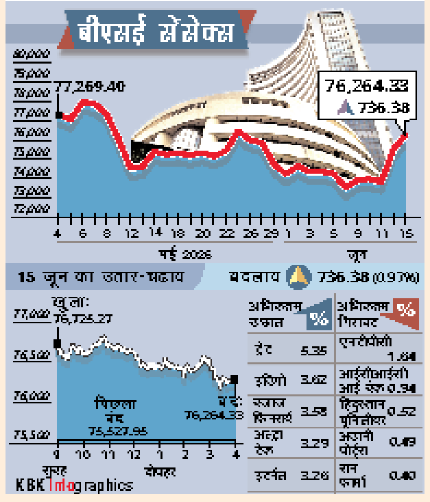

■ **सेंसेक्स 0.97 प्रतिशत ऊपर 76,264.33 अंक पर रहा**

■ **निफ्टी 0.98 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,853.90 अंक पर रहा**

मुंबई, 15 जून (एजेंसियां)। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद लिवाली से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 736 अंक चढ़कर तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

सेंसेक्स 1,197 अंक की तेजी में खुला और कुछ ही देर में 1,293 अंक चढ़ गया था। बाद में इसकी बढ़त कुछ कम हुई और यह 736.38 अंक (0.97 प्रतिशत) ऊपर 76,264.33 अंक पर बंद हुआ जो 25 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 231 अंक यानी 0.98 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,853.90 अंक पर रहा। यह 27 मई के बाद का इसका उच्चतम बंद स्तर है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर हमले बंद करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की भी बात कही गई है। समझौते पर 19 जून को स्विटजरलैंड में एक औपचारिक समारोह में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। वहीं, कच्चा तेल और अमेरिकी डॉलर दबाव में हैं। रुपए में भी आज मजबूती बनी हुई है। घरेलू स्तर पर वृहत बाजार में प्रमुख सूचकांकों से ज्यादा तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.36 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.09 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। चौतरफा लिवाली के बीच रियल्टी सेक्टर का सूचकांक चार प्रतिशत से ज्यादा और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद सेक्टर का करीब तीन प्रतिशत चढ़ा। ऑटो, वित्त, धातु और तेल एवं गैस समूहों के सूचकांक भी एक से तीन प्रतिशत के बीच चढ़े।

एनएसई में जिन 3,453 कंपनियों के शेयरों में आज कारोबार हुआ उनमें से 2,510 के शेयर हरे निशान में और 830 के लाल निशान में रहे। अन्य 113 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित बंद हुए।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 22 में तेजी रही। ट्रेंट का शेयर सबसे अधिक 5.35 प्रतिशत चढ़ गया। इंडिगो में 3.59 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 3.58, अल्ट्राटेक सीमेंट में 3.29, इटरनल में 3.26, मारुति सुजुकी में 3.25 और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.01 प्रतिशत की मजबूती देखी गयी।

एलएंडटी का शेयर 2.99 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस का 2.69, टाइटन का 2.27, इंफोसिस का1.68, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1.11, भारती एयरटेल का 1.00, आईटीसी का 0.98 और एक्सिस बैंक का 0.93 प्रतिशत की बढ़त में रहा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बीईएल, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी हरे निशान में रहे। एनटीपीसी का शेयर 1.64 प्रतिशत टूट गया। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनीलिवर और अडानी पोर्ट्स में भी गिरावट रही। वैश्विक स्तर पर एशिया में जापान का निक्केई 4.99 प्रतिशत, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.61 प्रतिशत और हांगकांग का हैंग सेंग 0.50 प्रतिशत की बढ़त में बंद हुआ।

मुंबई रिडेवलपमेंट से 2031 तक करीब 59 हजार नए घर होंगे तैयार : रिपोर्ट

■ **शहर अलग-अलग घरों से बड़ी बिल्डिंग की तरफ हो जाएगा शिफ्ट**

मुंबई, 15 जून (एजेंसियां)। मुंबई रिडेवलपमेंट पाइपलाइन से 2031 करीब 59,000 नए घर तैयार होंगे और इनकी वैल्यू 1.50 लाख करोड़ रुपए होगी। इस दौरान शहर अलग-अलग घरों से बड़ी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। प्रोपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सोसाइटी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से 9,115 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी सरकार को मिल सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2026 की शुरुआत में रिडेवलपमेंट गतिविधियां मजबूत रही है। यह इस बात से अधिक स्पष्ट होता है कि इस साल के पहले 90 दिनों में करीब 70 डेवलपर एग्रीमेंट (डीए) हुए हैं, जो कि पूरे 2025 में हुए कुल एग्रीमेंट्स का 30 प्रतिशत है।

मुंबई में डीए का आंकड़ा 2020 से पहली बार 1,050 के आंकड़े के पार निकल गया है। इसके साथ 1,094 सोसाइटी फिलहाल रिडेवलपमेंट में हैं, जिसमें 432 एकड़ भूमि पर काम चल रहा है। रिडेवलपमेंट का काम तेजी से मुंबई के उपनगरों में केंद्रित हो रहा है, जहां पाइपलाइन का 95 प्रतिशत हिस्सा है। इसमें वेस्टर्न सबर्ब्स सबसे आगे हैं, जहां 773 सोसायटियों का रिडेवलपमेंट हो रहा है, और उसके बाद सेंट्रल सबर्ब्स का नंबर आता है, जहां 261 सोसायटियां हैं। रिपोर्ट में शहर में बढ़ती शहरी आबादी के घनत्व और पुराने होते हाउसिंग स्टॉक (आवासों) का जिक्र किया गया है। मुंबई में लगभग 1.6 लाख इमारतें 30 साल से अधिक पुरानी हैं और उन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए चुना गया है।

सार संक्षेप

कोटक म्यूचुअल फंड ने पेश किया अपना पहला एसआईएफ

नई दिल्ली। कोटक म्युचुअल फंड ने अपने पहले स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) 'कोटक इनफिनिटी हाईब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड' की सोमवार को घोषणा की। नया फंड 15 जून से निवेशकों के लिए खुल गया है और इसका न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 29 जून तक उपलब्ध रहेगा। एसआईएफ निवेश की एक नयी श्रेणी है। यह पारंपरिक म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस तथा वैकल्पिक निवेश फंड जैसे उन्नत निवेश उत्पादों के बीच की खाई को पाटता है। यह श्रेणी पोर्टफोलियो निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्रदान करती है, हालांकि यह नियामकीय प्रावधानों के अधीन होती है। ऐसे निवेश उत्पाद उन निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं जो इनके जोखिम और विशेषताओं को अच्छी तरह समझते हैं। कंपनी ने बताया कि कोटक इनफिनिटी हाईब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह विभिन्न बाजार परिस्थितियों में इक्विटी जोखिम का सतत प्रबंधन कर सके।

यात्री वाहनों की बिक्री मई में नए रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री ने 4,38,854 इकाई के साथ मई महीने का नया रिकॉर्ड बनाया। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई में कंपनियों ने कुल 4,38,854 यात्री वाहन बेचे। यह एक साल पहले की 3,44,656 इकाई की तुलना में 27.3 प्रतिशत अधिक है और मई माह का नया रिकॉर्ड है। यात्री वाहनों में कारों, उपयोगी वाहनों और वैन को शामिल किया जाता है। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि यात्री वाहनों, तिपहिया और दुपहिया की बिक्री ने मई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। दुपहिया की बिक्री भी 14.8 प्रतिशत बढ़कर 19,02,209 इकाई के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसमें स्कूटरों की बिक्री में 27.4 प्रतिशत का, मोटरसाइकिलों में 7.2 प्रतिशत और मोपेड में 30.3 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।

नए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से महंगाई की निगरानी होगी मजबूत

नई दिल्ली। अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों ने सोमवार को सरकार द्वारा नए उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) फ्रेमवर्क को लागू किए जाने का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे महंगाई की निगरानी और मजबूत होगी, उद्योग स्तर पर कीमतों की बेहतर ट्रैकिंग संभव होगी और भारत की सांख्यिकीय प्रणाली वैश्विक मानकों के अनुरूप बनेगी। सरकार ने संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) सीरीज के साथ-साथ आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (ओपीपीआई), ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (आईपीपीआई) और सेवा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) को 2022-23 को आधार वर्ष बनाकर लागू किया है, जो देश के मुद्रास्फीति माप ढांचे में एक बड़ा बदलाव है।

चावल, गेहूं तेज, चीनी नरम, दालों व खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 15 जून (एजेंसियां)। घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल का औसत भाव बढ़ गया। चावल के साथ गेहूं में भी तेजी रही। चीनी की कीमतों में नरमी रही जबकि दालों और खाद्य तेलों उतार-चढ़ाव का रुख देखा गया। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 66 रुपए बढ़कर 3,897 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। गेहूं 11 रुपए मजबूत हुआ और 2,782 रुपए प्रति क्विंटल बोला गया। आटे की कीमत 20 रुपए टूट गई।

मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में अगस्त का पाम ऑयल वायदा 25 रिंगिट गिरकर 4,450 रिंगिट प्रति टन रह गया। जुलाई का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 1.86 प्रतिशत टूटकर 72.90 सेंट प्रति पौंड के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में सूरजमुखी तेल की औसत कीमत 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई। पाम ऑयल 83 रुपए और वनस्पति 67 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हुआ। सोया तेल में 42 रुपए और मूंगफली तेल में नौ रुपए की तेजी रही। सरसों तेल 115 रुपए प्रति क्विंटल फिसल गया। मीठे के बाजार में गुड़ का औसत भाव 56 आज प्रति क्विंटल गिर गया। चीनी भी 26 आज सस्ती हुई।

सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे : **दाल-दलहन :** दाल चना 7688.34 रुपए, मसूर काली 8130.44 रुपए, मूंग दाल 10144.49 रुपए, उड़द दाल 10910.92 रुपए, तुअर दाल 11185.49 रुपए प्रति क्विंटल रही।

अनाज : (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2781.94 रुपए और चावल 3897.13 रुपए प्रति क्विंटल और आटा (गेहूं) 3249.32 रुपए प्रति क्विंटल रहा। **चीनी-गुड़ :** चीनी एस 4342.44 रुपए और गुड़ 5046.24 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए।

मई में भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में हुई गिरावट

■ **समग्र स्तर पर बेरोजगारी दर में कोई बदलाव नहीं**

■ **ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 5.1 प्रतिशत पर स्थिर**

नई दिल्ली, 15 जून (एजेंसियां)। भारत के शहरी इलाकों में 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर मई 2026 में घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई है, जो पिछले साल इसी महीने में 6.9 प्रतिशत थी। साथ ही, इस दौरान शहरी इलाकों में महिलाओं की बेरोजगारी दर भी घटकर 8.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई। यह जानकारी सोमवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी डेटा में दी गई।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि समग्र स्तर पर बेरोजगारी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 5.1 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है।

कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) मई में 54.4 प्रतिशत दर्ज की गई है यह पिछले साल इसी महीने में 54.8 प्रतिशत थी, यानी इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह, कुल कामगारों की भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) इस महीने 51.4 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि पिछले साल मई में यह 51.7 प्रतिशत थी।

एनएसओ द्वारा किया जाने वाला 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (पीएलएफएस), आबादी की गतिविधियों में भागीदारी और रोजगार व बेरोजगारी की स्थितियों से जुड़े डेटा का मुख्य स्रोत है।

एनएसओ ने देश के लिए श्रम बल संकेतकों के मासिक और तिमाही अनुमान उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2025 से पीएलएफएस सर्वे की कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, चालू वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान शहरी बेरोजगारी में कमी आई, जबकि ग्रामीण रोजगार में द्वितीयक और तृतीयक दोनों क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई।

15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शहरी इलाकों में कुल बेरोजगारी दर में गिरावट का रुझान दिखा, जनवरी-मार्च तिमाही में यह 6.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7 प्रतिशत थी। पीएलएफएस के नतीजे हर महीने बुलेटिन के रूप में जारी किए जाते हैं।

सार-समाचार

प्रसिद्ध लेखिका इंदिरा लंकेश का निधन

बेंगलुरु, देशबन्धु। दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और प्रसिद्ध लेखिका-उद्यमी इंदिरा लंकेश का 83 वर्ष की आयु में सोमवार 15 जून की सुबह बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा था। लंकेश के पति कन्नड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार पी. लंकेश थे। गौरी लंकेश की मां होने के साथ-साथ, इंदिरा एक लेखिका भी थीं। उनके जीवन के संस्मरण, विशेष रूप से 'हुलीमावु मद्दु नानू' को कन्नड़ साहित्य में महिला लेखकों के संस्मरणों के रूप में एक मील का पत्थर माना जाता है। उल्लेखनीय है कि इंदिरा लंकेश की बेटी गौरी लंकेश एक मुखर पत्रकार और कार्यकर्ता थीं, उनकी सितंबर 2017 में बेंगलुरु स्थित घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद, इंदिरा लंकेश ने नौ साल तक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए चले अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

री-नीट प्रश्नपत्र के नाम पर छात्रों से ठगी, दो गिरफ्तार

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात पुलिस की अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है व राजस्थान के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए री-नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर एक हजार से अधिक छात्रों और उनके अभिभावकों से करोड़ों की ठगी की। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 319 (2), 54 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आंध्र में खड़ी लॉरी से बाइक टकराने से तीन युवकों की मौत

अनंतपुर, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के मदकशिरा मंडल के तडाकलापल्ली गांव में सोमवार को एक खड़ी लॉरी से बाइक टकराने से तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तीनों युवक मोटर साइकिल से मदकशिरा से हिंदूपुर जा रहे थे। उनकी बाइक एक खड़ी लॉरी से टकरा गई। मृतकों की पहचान आदिनारायण, महेंद्र और त्रिलोक के रूप में हुई है और सभी की उम्र 25 साल से कम थी। आदिनारायण और महेंद्र की तुरंत जबकि त्रिलोक की मौत बैंगलोर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है।

पटना उच्च न्यायालय में सात नए न्यायाधीशों ने ली शपथ

पटना, एजेंसियां। पटना उच्च न्यायालय में सोमवार को सात नये न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। इसके साथ ही न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 44 हो गई। मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने इन न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने 10 जून को अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया था, जबकि अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजेश कुमार और अधिवक्ता आलोक कुमार को पद भार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया था। शपथ ग्रहण समारोह में न्यायालय के न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बड़ी संख्या में अधिवक्ता, विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी और नवनियुक्त न्यायाधीशों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इन सात न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 53 है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने गत 26 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय के नौ अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी।

जनसम्पर्क अभियान - ईवी स्कूटर से भीमनगर पहुंचे मुख्यमंत्री, जनता से किया संवाद

12वीं की टॉपर चांदनी से मिले, बोले - यह उपलब्धि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत

ईवी केवल पेट्रोल के दाम ही नहीं बचाती, बल्कि हमारे कई अन्य तरह के खर्चे भी कम करती है। इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी और भाजपा जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति भी मौजूद थे।

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत राजधानी भोपाल के भीम नगर पहुंचे। उन्होंने यहां लोगों से संवाद किया और उनका हाल-चाल जाना। डॉ. यादव ने इस संवाद के लिए काफिला छोड़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल किया। इस मौके पर वे एमपी बोर्ड की बारहवीं की टॉपर चांदनी विश्वकर्मा के घर भी गए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने परिवार के साथ बातचीत की। उन्होंने परिजनों के साथ सेल्फी भी ली।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चांदनी ने विषम परिस्थितियों के बीच भी अपने परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से जो सफलता अर्जित की है, वह प्रेरणादायी है। उनकी उपलब्धि न सिर्फ अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है।

डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर हमने पार्टी पदाधिकारियों के साथ यहां जनता से संवाद किया। लोगों ने बताया कि डॉ. यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जिंदगी भविष्य में और भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री खुद ईवी स्कूटर चलाकर भीमनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसे चलाकर अच्छा भी लगा।

जनता रह गई अचंभित: मुख्यमंत्री के पहुंचते ही भीम नगर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अमूमन अपने-अपने कामों में मशरूफ रहने वाले भीम नगर के लोग आज बेहद उत्साहित और जागरूक दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अचानक अपने सामने देख लोग अचंभित हो गए। इस बीच उन्होंने लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। डॉ. यादव ने बेटियों को गोद में लेकर दुलार किया और सेल्फी ली।

खेती- सौर ऊर्जा का संगम: भारत और जर्मनी में हुआ समझौता

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के समन्वित विकास की दिशा में सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा जर्मन सरकार समर्थित इंडो-जर्मन एग्रीवोल्टाइक सहयोग परियोजना (आईजीसीए) के बीच मंत्रालय में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत प्रदेश में एग्री सौर पीवी (एग्रीवोल्टाइक) परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी।

किसानों को खेती के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन से मिलेगी अतिरिक्त आय

एग्रीवोल्टाइक मॉडल के अंतर्गत किसान अपनी कृषि भूमि पर खेती जारी रखते हुए उसी भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन भी कर सकेंगे। इससे अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी और किसानों को खेती के साथ ऊर्जा उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी, जबकि भूमि का स्वामित्व किसानों के पास ही रहेगा। समझौते के तहत जर्मन सहयोगी संस्था परियोजनाओं की पहचान, तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन, डिजाइन, वित्तीय व्यवहार्यता तथा क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, ऊर्जा विकासकर्ताओं, डिस्कॉम और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक अमनवीर सिंह बैंस, भारत में जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि, एग्रीवोल्टाइक संगठन के एलेक्जेंडर तथा जर्मनी की जीआईजेड कम्पनी के अधिकारी उपस्थित रहे। यह पहल किसानों के लिए डबल लाभ का मॉडल साबित हो सकती है, जिसमें खेत से फसल और उसी खेत से बिजली उत्पादन दोनों के जरिए आय के नए स्रोत विकसित होंगे।

मंदसौर में कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन

भाजपा कार्यालय घेरने निकले कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार, लाठीचार्ज भी

मंदसौर, देशबंधु। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा सांसद का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में सोमवार को मंदसौर में युवक कांग्रेस ओर एनएसयूआई द्वारा सोमवार को उग्र प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद से पानी की बौछार की तथा बाद में हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान 2 से 3 कार्यकर्ता के मामूली रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। पार्टी के जिला कार्यालय से कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए रैली के रूप में रवाना हुए। जिन्हें गांधी चौराहे से बालाजी मंदिर के बीच पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस दौरान पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पहले समझाइश दी, लेकिन नहीं मानने पर फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी की बौछार की गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस

चुनाव आयुक्त के पुतले फूंके, पुलिस ने कई जगह किया बल प्रयोग

भोपाल, देशबन्धु। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का आंदोलन तेज हो गया है। इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंके। आदांलनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई। इस दौरान कई जगह पुलिस और आंदोलनकारी युवाओं के बीच झड़प भी हुई। जिसके चलते पुलिस को कहीं बल प्रयोग भी करना पड़ा और पानी की बौछार भी छोड़नी पड़ी।

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया के निर्देश पर प्रदेशभर में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। युवा कांग्रेस ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, सतना, मुरैना, कटनी मंदसौर सहित सभी जिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंककर विरोध दर्ज कराया। घनघोरिया ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक निष्पक्षता खो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधारों पर निरस्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश का हिस्सा है। घनघोरिया ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई है। सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद मंगलवार को एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन करेगी, जबकि बुधवार को महिला कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलेगी।

खनिज और राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, 101 कर्मियों के तबादले

भोपाल, देशबन्धु। राज्य शासन ने खनिज साधन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए अधिकारी से लेकर भृत्य स्तर तक कुल 101 कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरण सूची 15 जून की रात जारी की गई।जारी आदेश के अनुसार खनिज साधन विभाग में 10 सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, 6 सहायक मानचित्रकार, 5 सर्वेक्षक, 4 सहायक भौतिकीविद, 2 प्रभारी अधिकारी, 14 सहायक खनिज अधिकारी, 9 खनिज निरीक्षक, 1 अधीक्षण भौमिकीविद तथा 1 भृत्य का तबादला किया गया है। वही इसके अलावा राजस्व विभाग में भी 39 पटवारियों, 7 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, 1 राजस्व निरीक्षक तथा 2 भृत्यों के स्थानांतरण किए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विभागीय कार्यों में गति लाने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह तबादले किए गए हैं। स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारतीय नाविकों की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराएं प्रधानमंत्री : कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसियां। कांग्रेस ने अमेरिकी हमले में भारतीय जहाज के चालक दल के तीन सदस्यों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने और इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि भारतीय नागरिकों की हत्या पर प्रधानमंत्री को शोक व्यक्त करने के साथ ही समुद्री सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करानी चाहिए। कांग्रेस सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विभाग प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज करने के साथ ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान की भी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने हमले में मारे गए हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा, उत्तर प्रदेश के शिवानंद चौरसिया और आंध्र प्रदेश के पटनाला सुरेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नाविकों के परिवार गहरे सदमे में हैं और पूरे देश में शोक का माहौल है।

नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया मूल रूप से बांग्लादेश की पार्टी : रंजन

कोलकाता, एजेंसियां। नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के फेसबुक पोस्ट शेयर करने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 20 बागी सांसदों के साथ एनसीपीआई पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी संसदीय ताकत बनकर उभरी है। इसके बाद कांग्रेस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब स्थिति पहले से ज्यादा विकट हो चुकी है। पहले सिर्फ बांग्लादेश के नागरिक ही भारत में अवैध रूप से दाखिल होते थे, लेकिन अब राजनीतिक दल भी हो रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी नेताओं के त्रिपुरा की एनसीपीआई में शामिल होने का जिक्र करते हुए दावा किया कि यह पार्टी मूल रूप से बांग्लादेश की है, जिसका उदय ही शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोलने के मकसद से हुआ था। इस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीं पर अपनी दस्तक दी और आज यह त्रिपुरा में अपनी जगह बना चुकी है। अब इसी पार्टी में टीएमसी के कई बागी नेता भी शामिल हुए हैं। उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो इस पार्टी की जांच करें। इस पार्टी की जरूरी इसलिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश के नागरिकों के इतर वहां के राजनीतिक दल भी अवैध रूप से यहां पर दाखिल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को चिन्हित करना मौजूदा सरकार के लिए जरूरी हो जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा

खाद वितरण प्रणाली में बढ़ रहा माफिया का प्रभाव

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संकट किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद वितरण प्रणाली में बिचौलियों और माफिया नेटवर्क का प्रभाव बढ़ रहा है।

पटवारी ने पत्र में खरीफ सीजन में पूरे प्रदेश में खाद और डीजल की भारी कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खेतों में बुवाई की तैयारी की बजाय खाद की लंबी कतारों में खड़े होकर मानसून का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि खाद-डीजल संकट पर तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जिलावार खाद स्टॉक और वितरण की दैनिक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और सभी संभागों में किसानों के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं। पटवारी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर-चंबल और नर्मदापुरम-भोपाल संभाग समेत पूरे प्रदेश के किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा और रतलाम में सहकारी समितियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। उन्होंने किसानों को निर्धारित मात्रा से कम खाद देने का भी आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर के किसान कपास और सोयाबीन की बुवाई की तैयारी छोड़कर डीजल और खाद के लिए भटक रहे हैं।

मोहनजोदड़ो की 'नृत्यांगना' प्रतिमा को लेकर नया विवाद

मूल स्वरूप में चित्र प्रकाशित करने की तैयारी

भोपाल/नई दिल्ली, देशबन्धु। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कक्षा नवमी की नवीन कला शिक्षा पुस्तक में सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध 'नृत्यांगना' प्रतिमा के परिवर्तित चित्र को लेकर उठे विवाद के बीच अब प्रतिमा के मूल स्वरूप वाले चित्र को पुन: प्रकाशित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, आपत्तियों और व्यापक चर्चा के बाद परिषद इस विषय की समीक्षा कर रही है तथा संशोधित चित्र के स्थान पर प्रतिमा का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है।

दरअसल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित 'नृत्यांगना' प्रतिमा भारतीय पुरातत्व और प्राचीन कला की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में गिनी जाती है। कक्षा नवमी की नई कला शिक्षा पुस्तक में प्रकाशित चित्र में प्रतिमा के ऊपरी भाग को ढका हुआ दिखाया गया था, जिसके बाद इतिहासकारों, शिक्षाविदों और कला विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक तथ्य और मूल कलाकृति के स्वरूप से छेड़छाड़ बताया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रतिमा लगभग साढ़े चार हजार वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट कलाकृति है और इसे उसी रूप में विद्यार्थियों के सामने रखा जाना चाहिए, जिस रूप में वह पुरातात्विक धरोहर के रूप में उपलब्ध है। कई विद्वानों ने तर्क दिया कि ऐतिहासिक धरोहरों के मूल स्वरूप में परिवर्तन से विद्यार्थियों तक तथ्यों की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। विवाद बढ़ने के बाद परिषद के स्तर पर समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई है। जानकारी के अनुसार, अब पुस्तक में प्रयुक्त परिवर्तित चित्र को हटाकर प्रतिमा का मूल चित्र शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो की 'नृत्यांगना' प्रतिमा भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन कला, धातु शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी धरोहरों का अध्ययन उनके वास्तविक स्वरूप में ही कराया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को इतिहास और कला की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो सके।

अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई

सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा राम मंदिर दान चोरी का मामला

अखिलेश ने उठाया था मामला, चर्चा का विषय बना

नई दिल्ली, एजेंसियां। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस संबंध में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित हेराफेरी की जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कथित अनियमितताओं के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच कराने पर भी विचार करने की मांग की गई है। याचिका में दान और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई गई है। यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उठाए जाने के बाद व्यापक चर्चा का विषय बना। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं साधु-संतों के बयान भी सामने आए, जिससे यह विवाद और सुर्खियों में आ गया।

विवाद बढ़ने पर यूपी सरकार ने बनाई एसआईटी: मामले के तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। इस टीम में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सोमवार को कहा कि दान राशि में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी द्वारा किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट जांच में पूरा सहयोग करेगा और एसआईटी को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में उनकी रविवार को जिला प्रशासन से बातचीत हुई थी और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

सूचना का अधिकार बना नया धंधा : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली, देशबन्धु। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार के नाम पर सक्रियता अब एक नया धंधा बनता जा रहा हैं । न्यायालय ने सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोपित एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने आरोपी राकेश कुमार बहल को राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि आजकल सूचना के अधिकार की सक्रियता एक नया व्यवसाय बन गई है। पीठ ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित शासकीय एजेंसियों की है। न्यायालय की इस टिप्पणी को सूचना के अधिकार के दुरुपयोग को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि. के लिए गिरिराज चाचा द्वारा श्री सिद्धि विनायक प्रिंटर्स, प्लाट नं. 26 बी देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं प्रकाशित, संपादक: पलाश सुरजन, कार्यकारी संपादक: ज़ाकिर अली* फोन 0755-4222971, ई-मेल deshbandhubpl1@yahoo.co.in प्रेस पंजीयन-प.स. 45096/85 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।